जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

कोटा

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

कोटा, शनिवार 9 मई, 2026

आन्दोलन अशुद्ध के विरुद्ध

KEDIA™ Pavitra

FIXED PRICE

250 g
MRP ₹ 250

विश्व की सर्वोत्तम हल्दी
7–12% CURCUMIN वाली
CRYOGENIC GRINDING से बनी
भारत की एकमात्र लाकाडोंग हल्दी पाउडर
(साधारण हल्दी से 4 गुना ज्यादा करक्यूमिन)

क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग से बने प्रोडक्ट्स
लाकाडोंग हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर

लाकाडोंग हल्दी पाउडर
मेघालय के लाकाडोंग की पहाड़ियों में उगाई गई प्रीमियम GI TAGGED हल्दी से बना

ब्लैंडेड मसाले
किचन किंग मसाला • गरम मसाला • सब्ज़ी मसाला • शाही पनीर मसाला
दाल मखनी मसाला • राजमा मसाला • चना मसाला • पाव भाजी मसाला • सांभर मसाला
चाट मसाला • छाछ मसाला • रायता मसाला • जलजीरा मसाला • पोहा मसाला
चाय मसाला • अमचूर पाउडर • हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट • तूफानी हींग

कॉल लगाओ, गाड़ी बुलाओ
1800-120-2727

For joining us as Distributor or Business Development Officer
Email ID : bdm@kediapavitra.com | Call : +91 76888-66333

ORDER ON WEBSITE | ORDER ON WHATSAPP | ORDER ON APP | ORDER ON ZEPTO

*T&C Apply. MRP ₹ incl. of all taxes

www.rera.rajasthan.gov.in | RERA No. RAJ/P/2023/2387

FIXED PRICE

₹4000/- Sq Ft में फ्लैट !

NO MIDDLE MEN

वैशाली की रेट
12000/- Sq. Ft.

8 मिनट की दुरी की रेट
4000/- Sq. Ft.

8 मिनट में
8000/- Sq. Ft. की बचत

अब हर महीने रेट बढ़ेगी

PRODUCT TYPE	UNIT TYPE	SIZE	PRESENT RATE	31 MAY 2026	30 JUNE 2026	31 JULY 2026	31 AUG. 2026	30 SEPT. 2026	31 OCT. 2026	30 NOV. 2026	30 DEC. 2026
WALK-UP APARTMENT	2 BHK (GF)	1350 Sq Ft	65 Lacs	66 Lacs	68 Lacs	70 Lacs	72 Lacs	74 Lacs	76 Lacs	78 Lacs	80 Lacs
	3 BHK (SF)	1900 Sq Ft	75 Lacs	76 Lacs	78 Lacs	80 Lacs	82 Lacs	84 Lacs	86 Lacs	88 Lacs	90 Lacs
	3 BHK (FF)	1900 Sq Ft	80 Lacs	82.5 Lacs	85 Lacs	87.5 Lacs	90 Lacs	92.5 Lacs	95 Lacs	97.5 Lacs	1 Cr
KOTHI	3 BHK BIG	2000 Sq Ft	1.05 Cr	1.075 Cr	1.10 Cr	1.125 Cr	1.15 Cr	1.175 Cr	1.20 Cr	1.225 Cr	1.25 Cr
	4 BHK BIGGER	2325 Sq Ft	1.26 Cr	1.29 Cr	1.32 Cr	1.35 Cr	1.38 Cr	1.41 Cr	1.44 Cr	1.47 Cr	1.50 Cr
	4 BHK BIGGEST	3200 Sq Ft	1.60 Cr	1.65 Cr	1.70 Cr	1.75 Cr	1.80 Cr	1.85 Cr	1.90 Cr	1.95 Cr	2 Cr

KEDIA®
1800-120-2323
info@kedia.com
www.kedia.com
78770-72737

SCAN QR FOR
• LOCATION
• ROUTE MAP
• SITE 360 TOUR
• E-BROCHURE
• WALKTHROUGH

*T&C Apply

विचार बिन्दु

सत्ग्रंथ इस लोक की चिंतामणि हैं उनके अध्ययन से सारी कुचिंताएं मिट जाती है। संशय पिशाच भाग जाते हैं और मन में सदभाव जागृत होकर परम शांति प्राप्त होती है। -अज्ञात

पेंशन के लिए पैसा नहीं, मुफ्त की रेवड़ियों के लिए खजाना खुला है - राजस्थान के विश्वविद्यालय पेंशनरों के साथ अन्याय कब तक?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा- पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचो, 'लाड़की बहन' जैसी योजनाएं बंद करो। अदालत का यह आदेश केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा। पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, 43000 करोड़ रु. की लाड़की बहन जैसी योजना बंद करें-बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई ने स्पष्ट और सख्त शब्दों में कहा है कि फंड की कमी का बहाना बनाकर सरकार या नगर निगम प्रशासन पेंशन और बकाया लाभों का भुगतान टाल नहीं सकता। अदालत ने यहां तक कह दिया कि अगर पैसे नहीं हैं तो गैर-जरूरी योजनाएं बंद करें या दफ्तरों की संपत्ति बेचें, लेकिन कर्मचारियों को उनका हक जरूर दें।

यह टिप्पणी सातवें वेतन आयोग लागू होने से परेशान एक सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। मुंबई नगर निगम के शिक्षा विभाग में कार्यरत रही एक महिला कर्मचारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा तब खटखटाया, जब सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन और अन्य वैधानिक लाभ नहीं मिले। बार-बार आग्रह के बावजूद नगर निगम और सरकार की ओर से केवल फंड की कमी का हवाला दिया जा रहा था, जिससे उनका जीवनयापन कठिन हो गया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासन की दोहरी नीति पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब अतिरिक्त आयुक्तों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार पूरा वेतन मिल सकता है, तब शिक्षकों और कर्मचारियों के मामले में अचानक फंड की कमी क्यों सामने आ जाती है। कोर्ट ने कहा कि जब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का समय आ चुका है, तब भी सातवां वेतन आयोग लंबित रखना गंभीर लापरवाही है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार के पास सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन देने के लिए धन नहीं है, तो उसे 'लाड़की बहन' जैसी योजनाएं बंद करने पर विचार करना चाहिए। कर्मचारियों का वेतन और पेंशन कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि उनका कानूनी अधिकार है।

यह टिप्पणी राजस्थान सरकार और यहां के सभी विश्वविद्यालयों के लिए आईना है। यह खबर राजस्थान के विश्वविद्यालय पेंशनरों का दर्द बयान करती है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के पेंशनर 12 दिन से धरने पर हैं। 42.6 डिग्री तापमान में न छाया, न पानी की व्यवस्था। नतीजा-चार बुजुर्ग बेहोश होकर गिर पड़े। ओआरएस और दवाइयों से प्राथमिक उपचार करना पड़ा। पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रो. रामनिवास शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि किसी पेंशनर को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार होगी।

सवाल यह है-नौबत यहां तक क्यों आई? विश्वविद्यालय की सालाना आय 76 करोड़ है, जबकि खर्च 121 करोड़। यानी हर साल 45 करोड़ का घाटा। 1,475 पेंशनरों को सालाना 105 करोड़, यानी हर महीने 8.75 करोड़ रुपये पेंशन देनी पड़ रही है। पिछले 8 वर्षों में 16 बार आंदोलन हो चुके हैं, पिछले वर्ष जुलाई में 92 दिन लगातार आंदोलन हुआ। फिर भी हर दूसरे महीने धरना देना पड़ रहा है।

अच्छी बात है कि गरीबों को राहत मिले, लेकिन क्या यह राहत उन लोगों का हक मारकर दी जा रही है जिन्होंने जीवन भर सेवा की? कृषि विश्वविद्यालयों में स्थिति और भी गंभीर है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में 22 महीनों की पेंशन बकाया है। महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत के स्थान पर केवल 12 प्रतिशत दिया जा रहा है, वह भी अदालत के हस्तक्षेप के बाद। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही, सातवें वेतन आयोग का एरियर लंबित है, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही, कम्यूटेड पेंशन पर रोक है।

राजस्थान में आज स्थिति यह है कि लोक-लुभावन योजनाओं के लिए खजाना हमेशा खुला रहता है, लेकिन जिन शिक्षकों ने 35-40 साल तक राष्ट्र निर्माण किया, उनकी पेंशन के लिए फंड की कमी का रोना रोया जाता है। राज्य में अनेक योजनाएं चल रही हैं-लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, युवा स्वरोजगार योजना, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुफ्त बिजली योजना-इन पर हर साल 40-50 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय पेंशनरों के लिए 550 करोड़ रुपये नहीं हैं।

अच्छी बात है कि गरीबों को राहत मिले, लेकिन क्या यह राहत उन लोगों का हक मारकर दी जा रही है जिन्होंने जीवन भर सेवा की? कृषि विश्वविद्यालयों में स्थिति और भी गंभीर है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में 22 महीनों की पेंशन बकाया है। महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत के स्थान पर केवल 12 प्रतिशत दिया जा रहा है, वह भी अदालत के हस्तक्षेप के बाद। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही, सातवें वेतन आयोग का एरियर लंबित है, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही, कम्यूटेड पेंशन पर रोक है।

विडंबना यह है कि वर्तमान कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को 12-42 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। यह केवल वित्तीय संकट नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता का प्रमाण है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह पैसा आता कहां से है? यह पैसा ईमानदार टैक्सपेयर की जेब से आता है-वह मध्यम वर्ग जो सुबह 9 से शाम 6 तक मेहनत करता है, इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है। जब सरकार उसी पैसे से मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, नकद सहायता बांटती है, तो विकास के कार्यों में कटौती होती है। सड़कें टूटती हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, नहरों में पानी नहीं-क्योंकि पैसा रेवड़ियां बांटने में खर्च हो रहा है।

क्या यह टैक्सपेयर के साथ धोखा नहीं है? उसने टैक्स इसलिए दिया था कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे-न कि वोट बैंक बनाने के लिए पैसा बांटा जाए। मुफ्तखोरी समाज को आलसी बना रही है। युवा वर्ग में यह मानसिकता बन रही है कि सरकार देगी तो काम क्यों करें? यह राष्ट्र की उत्पादकता पर सीधा प्रहार है। स्वाभिमान से काम करके खाने की संस्कृति खत्म हो रही है और सरकार पर निर्भरता बढ़ रही है।

समाधान भी स्पष्ट है। सबसे पहले, पेंशन और वेतन को प्राथमिकता दी जाए-यह कोई दया नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है। दूसरे, फिजूलखर्ची पर रोक लगे-यदि पेंशन के लिए पैसा नहीं है तो गैर-जरूरी योजनाएं बंद हों। तीसरे, जवाबदेही तय हो-विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाए। उनके खर्चों में कटौती कर पेंशन दी जा सकती है।

अब सरकार को तय करना है-लोकप्रियता या न्याय? वोट बैंक या राष्ट्र निर्माण? मुफ्तखोरी या स्वाभिमान? बॉम्बे हाईकोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है। अब राजस्थान सरकार और विश्वविद्यालयों को निर्णय लेना है कि वे कुर्सी-टेबल बेचेंगे या पेंशनरों के आंसू पोंछेंगे। क्योंकि जिस देश में गुरु भूख के कगार पर हो और मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाएं, उस देश का भविष्य अंधकारमय होता है।

अंततः यह केवल आर्थिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों का प्रश्न है। जिस समाज में अपने शिक्षकों और वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़े, वहां विकास अधूरा रह जाता है। समय आ गया है कि सरकार यह तय करे-क्या वह रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देगी या उन लोगों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करेगी, जिन्होंने जीवन भर राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है।

-अतिथि सम्पादक,
प्रो. पी. सी. कंठालिया,
पूर्व विभागाध्यक्ष एवं मुख्य मृदा वैज्ञानिक,
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, उदयपुर

लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाना और को परिसीमन - राज्यों के शक्ति संतुलन को बचाकर न्यायसंगत प्रतिनिधित्व कैसे हो

महावीर सिंह

16,17 अप्रैल 26 को लोकसभा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बहस हुई। अवसर था नारी शक्ति को लोकसभा, विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व देना। वैसे तो महिलाओं के लिए ऐसा संविधान संशोधन पहले किया जा चुका था किंतु राम, जाने उसे तत्काल लागू क्यों नहीं किया गया था? क्या उसी संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं किया जा सकता था?? लेखक के अनुसार किया जा सकता था, कोई बाधा नहीं थी। इसे अनावश्यक रूप से जनगणना और डिलिमिटेशन से जोड़ा गया।

ऐसा क्यों किया गया? इस पर संसद में व्यापक चर्चा हो चुकी है। उसे दोहराने का कोई अर्थ नहीं होगा। सत्ता पक्ष महिलाओं का बड़े पैमाने पर समर्थन चाहता है और इस की आड़ में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों को मनमर्जी से पुनर्गठित करना चाहता था, ऐसा लगभग सम्पूर्ण विपक्ष का कहना था। निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन में, यदि आयोग निष्पक्षता से काम नहीं करे तो सत्ता पक्ष की इच्छाओं के अनुसार पटवार मंडलों, गिरदावर हलकों को इस ढंग से निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ और हटा सकता है जो एक बार तो सत्तापक्ष का पलड़ा भारी कर ही सकता है।

परिसीमन यानी लोकसभा और विधानसभा सीटों का फिर से बंटवारा 2026 के बाद का सबसे बड़ा संवैधानिक मुद्दा होगा। अभी 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें फ्रीज हैं। तब से दक्षिण-पश्चिम के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में कामयाबी पाई, जबकि उत्तर-मध्य के राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी। सिर्फ जनसंख्या को आधार बनाएंगे तो संसद में शक्ति संतुलन बिगड़ेगा। इसका हल क्या हो?

लोक सभा में 16-17 अप्रैल 2026 को 131वें संविधान संशोधन बिल और संबंधित Delimitation Bill पर बहस हुई। सरकार ने प्रस्ताव दिया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाए।सरकार का मानना था कि इस से महिला आरक्षण (33 %) को बिना किसी श्रेणी की कोई मौजूदा सीट घटाए लागू किया जा सकता है। वर्तमान 543 में ही सीधे 33 % आरक्षण लागू करें तो पुरुषों के लिए सीटें कम हो जाएंगी। इसलिए कुल सीटों को लगभग 50 ▯ बढ़ाकर (543+ 50% करीब 815-850) करने की बात बिल में रखी थी। अधिकतम 850 ऊपरी सीमा बताई गई थी। सीटों का पुनर्निर्धारण 2011 णहेले के आधार पर होना प्रस्तावित था।

आगे बढ़ें, इस से पहले कुछ दूसरे देशों में जनता से सीधे चुन कर आने वाले सदस्यों की सदनों में संख्याओं पर नजर डालना ठीक रहेगा :-फ्रांस में 577 सदस्य, जर्मनी में 630 सदस्य, रूस में450 सदस्य, चीन में 2,878 सदस्य इन सदनों में होते है। तुलना करते वक्त भारत और इन देशों की जनसंख्या को ध्यान में रखना चाहिएं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की सदस्य संख्या तय की गई है। प्रथम लोकसभा के लिए, 1950 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर औसतन एक सीट प्रति 7,20,000 जनसंख्या का आधार लिया गया था। पूरे देश के लिए कुल 401 निर्वाचन क्षेत्र बने और इस आधार पर पहला सार्वभौम वयस्क मताधिकार वाला चुनाव हुआ। 1951 जनगणना के आधार पर हुए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीटें बढ़कर 494 हो गई। 1963 में परिसीमन आयोग ने 1961 जनगणना के आधार पर और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन सीटें बढ़कर 522 हुई।1971 जनगणना के बाद सीटें बढ़कर 543 हुई और यही संख्या है।

1976 के 42वें संशोधन ने 1971 जनगणना के आधार पर सीटों का राज्य-वार आवंटन फ्रीज कर दिया इसे 2001 में 84वें संशोधन द्वारा 2026 तक बढ़ाया गया। 2002 Delimitation ने सीटों की कुल संख्या नहीं बदली, सिर्फ सीमाएं समायोजित कीं।

यह भी याद रखना होगा कि भारतीय संविधान में दूसरे संशोधन, 1952 की के द्वारा "not less than one member for every 750,000 of the population and" हटा दिया गए और इस प्रकार 7,50,000 की अधिकतम सीमा पूरी तरह हटा दी गई। केवल 5,00,000 की कम से कम जनसंख्या सीमा बनी रही जिसे भी बाद के संशोधनों में हटा दिया।

वर्तमान में कुछ प्रांतों की सीटों की स्थिति पर विचार करें। लोकसभा में 543 में से उत्तर प्रदेश के 80, बिहार 40, महाराष्ट्र 48 सीट, तमिलनाडु 39, केरल 20 सीट और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, केरल 9 सदस्य है। आशंका है कि 2026 के बाद अगर केवल जनसंख्या आधार माना तो ळङ्-बिहार की लोकसभा सीटें 200 पार कर सकती हैं। तमिलनाडु-केरल की सीटें आनुपातिक रूप से घटेंगी। इससे जिन राज्यों ने परिवार नियोजन लागू किया, उन्हें 'सजा' मिलेगी और राज्यों और केंद्र के तथा आपस में राज्यों के बीच अविश्वास बढ़ेगा।देश के संविधान में उल्लेखित संघवाद की भावना क्षीण होगी।

संविधान क्या कहता है

अनुच्छेद 81: लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में होगा।

अनुच्छेद 82: हर जनगणना के बाद परिसीमन होना है, पर 42वां और 84वां संशोधन कर 2026 तक इसे टाल दिया गया। अनुच्छेद 80: राज्यसभा राज्यों का सदन है, पर सदस्य संख्या जनसंख्या पर आधारित है।संविधान 'जनसंख्या' और 'संघीय संतुलन' दोनों की बात करता है। इसलिए इस गंभीर प्रश्न पर अत्यंत गंभीरता पूर्व मनन किया जाकर देश हित में निर्णय आवश्यक है। जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मान्यता भी मिले और राज्यों के बीच संघीय संतुलन भी कायम रहे। किसी राज्य को यह नहीं लगना चाहिए कि उसे प्रगतिशील नीतियों के सफल क्रियान्वयन करने की सजा मिल रही है। इसके साथ ही संघीय आय व राजस्व में पिछड़े, विशेष समस्याओं वाले राज्यों का उचित ख्याल रखा जाए।

इस संबंध में कई प्रस्ताव विभिन्न राजनीतिक दलों व नेताओं, स्वतंत्र विचारकों, संविधान के ज्ञाताओं के विचार संसद में, समाचार पत्रों में, टीवी चैनल्स पर सामने आए है।

एक प्रस्ताव है ----राज्यसभा में हर राज्य से 5,7 सांसद हों अर्थात राज्य सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार न हो। राज्य सभा 'राज्यों का सदन' है। उदाहरणार्थ अमेरिका की सीनेट में हर राज्य से 2 सदस्य होते हैं, चाहे कैलिफोर्निया हो या अलास्का। इससे छोटे राज्यों को संघ में बराबरी मिलती है।

क्या भारत में इस पर, किसी अन्य प्रकार से विचार किया जा सकता है? एक आधार हो सकता है, 250 सीटों में से हर राज्य/ को 1 या 2 या 3 सीट कुल 36/72/108 सीट मिलें। वर्तमान संख्या 350 में से बाकी 214 /178/142 सीटें क्षेत्रफल 25%, राजस्व योगदान 25%, मानव विकास सूचकांक 25%, अनुसूचित क्षेत्र/सीमावर्ती 25% के आधार पर बांटी जा सकती है। किसी राज्य विशेष के लिए अधिकतम सीमा 5 सदस्य प्रति राज्य रखी जा सकती । इस से सिक्किम, गोवा, नॉर्थ-ईस्ट की आवाज मजबूत होगी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र को भी जनसंख्या घटने की 'सजा' नहीं मिलेगी। हां, यह अवश्य है कि UP, बिहार जैसे राज्यों को लगेगा कि उनके प्रदेश का प्रतिनिधित्व घटा।

एक अन्य विकल्प यह हो सकता है कि संविधान संशोधन कर राज्यसभा को योजनाओं पर पूर्ण बहस व संशोधनों का अधिकार दिया जाए। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही पास होता है। राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है।

संविधान का अनुच्छेद 110 बदले बिना भी राज्य सभा में संसदीय समिति बनाकर की सभी 500 करोड़ से ऊपर की योजनाएं पहले राज्यसभा में विस्तृत बहस के लिए भेजी जा सकती है। इस से जिन योजनाओ का असर राज्यों पर पड़ता है, उन पर राज्यों के सदन को पूर्व-समीक्षा का अधिकार मिले। इससे संघीय भावना बढ़ेगी। संसाधन बंटवारे में वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यसभा में बहस व समर्थन अनिवार्य हो।

लोकसभा सीटों का राज्यों में वितरण के लिए भी

सिर्फ जनसंख्या से हटकर 'बहु-सूचकांक फॉर्मूला' अपनाया जा सकता।यदि केवल जनसंख्या को आधार मानें तो 10,15,20 लाख को जनसंख्या पर एक लोक सभा सीट निर्धारित हो तो संख्या इस प्रकार हो सकती है:-1420, 940, 720 ।

एक प्रस्ताव के अनुसार, 2026 की जनसंख्या के आधार पर संविधान में उल्लेखित कुल 543 की सदस्य संख्या का 50% अथवा अन्य कोई प्रतिशत जो संसद तय करे, उसके अनुसार, एक व्यक्ति एक वोट के अनुसार रखी जा सकती है। लोकसभा में 10% प्रतिनिधित्व क्षेत्रफल के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जिस से राजस्थान जैसे बड़े पर कम घनत्व वाले राज्यों का महत्व मिलेगा।

अन्य बिंदु जिन का लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर ध्यान रखा जा सकता है, वे यह हो सकते हैं :- राजस्व एकत्रीकरण:: ---महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जो जीएसटी-आयकर में 15▯ ज्यादा देते हैं, उन्हें महत्व मिलेगा। विकास व्यय गती::-- पिछले 10 साल में पूंजीगत व्यय के आधार पर अर्थात राज्य में पैसा जमीन पर लगाया उसके आधार पर। मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI + पिछड़ापना भी पैमाने में हो। केरल का ▯ ऊंचा है तो उसे इनाम मिलना चाहिए। बिहार, झारखंड का कम है तो उनको 'हैंड-होल्डिंग' के लिए सीट बढ़ा कर दी जा सकती है। किस बिंदु को कितना भार देना है, यह संसद तय करे।

सीट कैसे तय हो:---- एक उदाहरण के जरिए हम यों समझे सकते है::-कुल 543 सीट स्थिर रखें। हर राज्य का स्कोर् 0.5x जनसंख्या अंश + 0.1x क्षेत्रफल अंश +0.15 HDI के इंडेक्स के अनुसार +0.15 पिछड़ापन इंडेक्स के अनुसार...अथवा संसद द्वारा तय अन्य किसी अनुपात /वेटेज(महत्व, भार) में इन बिंदुओं को ध्यान में रख कर बनाया जाए और संसद से स्वीकृत हो। इस स्कोर पर सीट बांटी जा सकती है।

संतुलन के लिए 3 संवैधानिक सुरक्षा-कवच रखे जा सकते है। किसी भी राज्य की 1971 की सीटो से 10/20% से ज्यादा न घटे। इससे दक्षिण को भरोसा मिलेगा। राज्यों के अधिकार क्षेत्र की सूची वाले विधेयक राज्यसभा में 2/3 बहुमत से ही पास हों अर्थात कुछ मामलों में राज्यसभा को एक प्रकार का वीटों मिले।

दक्षिण-नॉर्थ-ईस्ट समूह का गठन किया जाए। लोकसभा-राज्यसभा में 10 से कम सीट वाले राज्यों का एक वैधानिक 'संसदीय समूह' बने और उसे लोकसभा में एक स्वतंत्र ग्रुप की हैसियत मिले । उसे प्रश्नकाल और अन्य महत्वपूर्ण सवालों पर होने वाली बहसों में उस समूह को समूह की सदस्यों की संख्या के अनुसार अतिरिक्त समय मिले। इसके लिए दक्षिण-नॉर्थ-ईस्ट ग्रुप को विशेष प्रकार की संसदीय अनुमति मिले।

आगे का रास्ता

1. परिसीमन आयोग 2026: इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, लोक सभा और राज्य सभा में पक्ष व प्रति पक्ष अथवा सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता द्वारा नामित एक एक सदस्य, केंद्रीय चुनाव आयोग के एक आयुक्त, नीति आयोग से एक सदस्य, राज्य के मुख्य सचिव आदि इसके सदस्य हों।

2. राष्ट्रीय बहस: 'जनसंख्या बनाम योगदान' पर सभी विधानसभाओं में प्रस्ताव पास कराएं।

3. संविधान संशोधन:अनुच्छेद 81,82,80 में 'बहु-सूचकांक' शब्द जोड़ें। इसके लिए 2/3 बहुमत ▯ आधे राज्यों की सहमति चाहिए।

निष्कर्ष यह माना जा सकता है कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाना और परिसीमन को अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता, पर 'सिर्फ हेड-काउंट' भारत जैसे संघीय देश में खतरनाक होगा। लोकसभा में 50▯ भार जनसंख्या को देकर बाकी 50अ भार क्षेत्रफल, राजस्व, ▯, पिछड़ेपन को दें। राज्यसभा को '1-5 फॉर्मूला' पर लाकर असली 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' बनाएं और उसे योजनाओ पर बहस, संशोधनों का अधिकार दें।

इससे UP-बिहार को बढ़ा प्रतिनिधित्व भी मिलेगा और तमिलनाडु-केरल को लगेगा कि उनके परिवार नियोजन की मेहनत बेकार नहीं गई। शक्ति संतुलन बचेगा, और संघीय ढांचा मजबूत होगा।

कुछ विद्वानों का यह भी सुझाव है कि संसद को जनहित के मुद्दों पर बहस ध्यानाकर्षण, स्वतंत्र विधेयक प्रस्तुतीकरण आदि के लिए ओर अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके लिए संसद की न्यूनतम अनिवार्य बैठको के दिन, संख्या संविधान संशोधन कर लाज़मी की जाएं। ब्रिटेन की संसद व्यवहारिक रूप से हर साल 100 से 150 दिन बैठकें करती है। फ्रांस में जनता का चुना हुआ सदन कमसे कम 120 दिन बैठकें करता है। जर्मनी का जनता से चुना सदन छुट्टियों को छोड़कर सदैव बैठता है। चीन की नेशनल पीपुल कांग्रेस साल में 1 बार 10 से 14 दिन बैठक करती है। रूस में दो सत्र होते है, ज़नवरी से जुलाई और सितम्बर से दिसंबर की अवधि में।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद की बैठकों पर विचार करें तो देखते है कि 2019 ए 2024 के बीच 17 वीं लोकसभा 5 साल में 274 दिन बैठी अर्थात 52 दिन सालाना औसत। 1952 से 1970 की अवधि में औसतन 120 से 140 दिन सालाना बैठकें हुई और यह लोकसभा बैठकों का सर्वोत्तम औसत स्कोर है।

543 की सदस्य संख्या पर ही सांसदों को अपनी बात रखने का बहुत कम समय मिलता है तो यदि विशुद्ध जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाकर सदस्य संख्या बढ़ाने जाएंगे तो लोकसभा व विधानसभाओं में सारे जनप्रतिनिधियों का क्या योग दान होगा, जब उन्हें पर्याप्त समय ही नहीं मिलेगा??? इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। संसद में ज्यादा अच्छे सुझाव, प्रस्ताव, विधेयक आएं, अच्छी गुणवत्ता वाली बहस हो तो यह लाज़मी होगा कि सालाना बैठकों की संख्या बढ़े, शून्य काल का समय बढ़े, प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश करने के लिए दिन तय हो।

पार्टीयों को समय देने के बजाए समय सदस्यों को आवंटित किया जाए।पार्टियां तो व्हिप जारी करती है और कुछ चुने हुए सांसदों को ही बोलने का मौका देती है। व्हिप के कारण अधिकांश सांसदों के स्वतंत्र विचार, सुझावों से देश और सदन महरूम रह जाता है।

एक अन्य सुझाव कई लोग देते है कि विधेयकों पर बहस के समय, बजट बहस के समय, सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव पर सदस्य अपने भाषण के दो भाग करें। सदन में मौखिक रूप से, वे अपने निर्धारित समय में केवल अपने भाषण, सुझावों के मुख्य बिंदु बोले तथा उनके संबंध में विस्तृत उदाहरण, फैक्ट्स आदि लिखित भाषण में संसद के पटल पर प्रस्तुत करदे जो सदन कार्यवाही विवरण में उनके भाषण का अंश हो जाए।इस से ज्यादा सांसदों को ज्यादा समय अच्छे सुझाव, अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को सदन में रखने का अवसर मिलेगा। एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए, 17 वीं लोकसभा में लगभग 50 बहस का समय केवल 15% सांसदों ने लिया, करीब 20% संसद 5 साल में एक बार भी नहीं बोले। ओर भी चौंकाने वाला आंकड़ा देख लें, 16 वीं, 17 वीं लोकसभा में क्रमशः 16, 22 समय हंगामों में गया। कई लोगों का यह भी विचार है कि चुने हुए जन प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों से ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रह सकें इसके लिए उन्हें साल में 1,2 बार 10,20 मिनट के लिए टीवी पर जनता से मुखातिब होने का समय दिया जा सकता है जिसका भुगतान सरकारें करें। इसको अधिक से अधिक सुनाने दिखाने की सुविधा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर स्क्रीन्स के जरिए की जा सकती है। इस से कुछ हद तक इस आपत्ति का हल हो सकता है कि 15,20 लाख की जनसंख्या के लगातार संपर्क में रहना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत मुश्किल कार्य है और इसलिए निर्वाचन क्षेत्र बढ़ाए जाने चाहिए।

-महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

डूंगरपुर जिले के बोखला पाल स्थित विद्यालय में शिक्षकों की कमी, छात्र परेशान

करीब 600 से ज्यादा विद्यार्थियों वाले इस स्कूल में वर्तमान में 16 शिक्षक कार्यरत हैं

डूंगरपुर, (निसं)। जिले के बोखला पाल स्थित चंदूलाल गुप्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है। यहां पिछले डेढ़ साल से 33 स्वीकृत पदों में से 17 पद खाली पड़े हैं। इस गंभीर स्थिति के कारण छोटी कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाने के लिए अब बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों को गुरुजी की भूमिका निभानी पड़ रही है।

करीब 600 से ज्यादा विद्यार्थियों वाले इस स्कूल में वर्तमान में 16 शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षकों की कमी के चलते विद्यालय में विषयवार पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में है। विद्यालय में हिंदी विषय के 3 पद, राजनीतिक विज्ञान के 2 पद, जबकि भौतिकी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के 1-1 पद लंबे समय से रिक्त हैं। इन महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों की अनुपस्थिति से छात्रों की शिक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है। शिक्षकों के अलावा विद्यालय में लाइब्रेरियकन, उप प्रधानाचार्य, अतिरिक्त एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जमादार और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के पद भी खाली पड़े हैं। स्टाफ की कमी से11 वीं और 12 वीं कक्षा के छात्र-छात्राएं छोटी कक्षाओं में अध्यापन कार्य करा रहे हैं।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 9 मई, 2026

प्रथम ज्येष्ठ मास (शुद्ध), कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2083, श्रवण नक्षत्र रात्रि 11:25 तक, शुक्ल योग रात्रि 2:36 तक, बव करण दिन 2:03 तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मकर, मंगल-मीन, बुध-मेष, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सवार्थ सिद्धि योग रात्रि 11:23 तक है। आज कालाष्टमी है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः शुभ 7:26 से 9:05 तक, चर 12:23 से 2:02 तक, लाभ-अमृत 2:02 से 5:20 तक।

राहूकालः 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:47, सूर्यास्त 7:00

मेष
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेंगी और व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों में व्यवधान हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

कर्क
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

सिंह
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी।

कन्या
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

तुला
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

धनु
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मकर
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण परामर्श मिल सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। समय अनर्गल कार्यों में खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

मीन
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 51 संख्याः 204 प्रभात कोटा, शनिवार 9 मई, 2026 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

अजीबो-गरीब तर्क दिए जा रहे हैं, वेणुगोपाल को मु.मंत्री बनाने के लिए

एक तर्क है कि आगामी यूपी चुनाव व 2029 के आम चुनाव की दृष्टि से पार्टी को हिन्दी भाषी संगठन महासचिव चाहिए, अतः वेणुगोपाल को संगठन महासचिव से हटाकर मु.मंत्री बनाकर, केरल भेज देना चाहिए

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 मई। केरल में भारी मतों से जीत के बाद कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चयन करने को लेकर भारी उलझन में है। हर नजरिए से के.सी. वेणुगोपाल इस रेस में आगे हैं, क्योंकि उन्होंने टिकटों का वितरण किया है और इस कारण कई विधायकों की कथित वफादारी उनके पक्ष में है।

लेकिन ज़मीन पर हकीकत कुछ और ही है।

केरल भर में कांग्रेस के लोग और यहां तक कि कांग्रेस के समर्थक और मतदाता के.सी. वेणुगोपाल के खिलाफ जुलूस निकाल रहे है और प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके पोस्टर और पुतले जला रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ खुला विरोध जता रहे हैं।

- अब, पुराना तर्क है कि विधायकों का बहुमत वेणुगोपाल के पक्ष में है, नहीं दोहराया जा रहा, क्योंकि सभी जानते हैं कि वेणुगोपाल ने केरल में टिकट बाँटे हैं। अतः विधायकों की सतही वफादारी वेणुगोपाल के पक्ष में तो होगी ही।
- विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन की टिकट वितरण में कोई भूमिका नहीं थी। अतः सतही तौर पर, सतीशन के पक्ष में बोलने वाले बहुत कम विधायक हैं। पर, सतीशन के सीपीएम सरकार के खिलाफ विधानसभा में पाँच साल तक चलाए गए संघर्षपूर्ण अभियान के लिए विधायकों में बहुत आदर है। अतः अगर सतीशन को मु.मंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस विधायक दल बिखर सकता है।
- क्या इस बिखराव का जोखिम उठाकर भी कांग्रेस वेणुगोपाल पर दांव लगाएगी?
- सतीशन, रमेश चैन्निथाला, वेणुगोपाल आदि को रविवार को दिल्ली बुलाया गया है तथा पार्टी के समक्ष दुविधा पर मंथन कर, समाधान निकालने की एक बार फिर चेष्टा होगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने छात्राओं की माँग तुरंत पूरी की

जयपुर/सीकर, 8 मई। 'बेटी पढ़े, बेटी बढ़े' की भावना को साकार करते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील कार्यशैली का एक अनूठा उदाहरण सामने आया है। जिला सीकर के ब्लॉक खंडेला स्थित जाजोद गांव की बालिकाओं ने रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री से जो मांग रखी, वह आज सुबह होते-होते पूरी हो चुकी थी। गुरुवार को रात्रि चौपाल के दौरान जाजोद गांव की कई छात्राएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलीं और अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने बताया कि उनके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोद में विज्ञान संकाय की सुविधा नहीं है, जिसके कारण उन्हें या तो मजबूरी में अन्य विषयों से पढ़ाई करनी पड़ती है या फिर विज्ञान पढ़ने के लिए घर से काफी दूर जाना पड़ता है। बालिकाओं की बात सुनकर मुख्यमंत्री ने तत्काल उन्हें आश्वासन दिया कि उनके स्कूल में विज्ञान संकाय अवश्य खोला जाएगा। रात को ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए।

- रात्रि चौपाल में छात्राओं ने विज्ञान संकाय की माँग की, मुख्यमंत्री ने सुबह संकाय खोलने की घोषणा कर दी।

शुक्रवार सुबह जब बालिकाएं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हमारे 300 से अधिक कार्यकर्ता को पीछा करके मारा गया था'

"उस समय शुभेन्दु अधिकारी ने पार्टी को बाँधे रखा था और तुरंत भाग कर वहाँ पहुँचते थे, जहाँ जब भी पार्टी संकट में होती थी"

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 मई। सभी अनिश्चितताओं को दरकिनार करते हुए शुभेन्दु अधिकारी को नव निर्वाचित भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया।

इसी बीच, कोलकाता में एक क्रांति चल रही है। न्यू टाउन क्षेत्र में कन्वेंशन सैंटर से दूर, नए मुख्यमंत्री की घोषणा की गई, कोलकाता की ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग, जो कभी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का इंपीरियल सेक्रेटेरियट हुआ करती थी, आज अपने मूल लाल रंग के ऊपर चमक रही केसरिया रोशनी में सजी हुई है।

वर्षों की उपेक्षा और खस्ता हालत के बाद, जब राइटर्स बिल्डिंग वीरान हो गई थी और राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ से शिफ्ट हो गया था, डलहौजी स्क्वायर आज रात एक रहस्यमय आभा बिखेर रहा है, जिसका प्रतिबिंब "लाल दीघी" (मानव निर्मित विशाल तालाब) में नज़र आ रहा है।

- इस माहौल में शुभेन्दु के अलावा किसी और को मु.मंत्री पद का उम्मीदवार बनाना, पार्टी में भारी निराशा व विरोध पैदा करता।
- इस अवसर पर बड़े सोच समझकर, कई पुरानी परम्पराएं पुनः जीवित की गई। शुभेन्दु अधिकारी के मु.मंत्री बनने की घोषणा ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग से की, जो कभी ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के साम्राज्य का शाही सचिवालय था। बीच में शासन न्यू टाउन एरिया के कन्वेंशन सैंटर से चलाया जाने लगा था, तथा राइटर्स बिल्डिंग वीरान सी पड़ी रहती थी।
- आज इस अवसर पर, पुराने स्मरणीय स्थल, जैसे, डलहौजी स्क्वायर, पश्चिम बंगाल के विधानसभा भवन को भगवा रोशनी कर जगमगाया गया था, जो कल तक लाल रंग में डूबा रहता था।

मानो राइटर्स बिल्डिंग से प्रतिस्पर्धा करते हुए, पश्चिम बंगाल विधानसभा भवन, जो कभी इंपीरियल लेजिस्लेचर हुआ करता था, भी केसरिया रंग में नहा रहा है।

और नई सरकार द्वारा सत्ता संभालने से पहले ही, राज्य-स्वामित्व वाले आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में हुई महिला डॉक्टर की मौत की जाँच के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

टीवीके के सभी 107 विधायकों ने इस्तीफा देने की धमकी दी थी

क्योंकि डीएमके और अन्नाद्रमुक के गठबंधन कर सरकार बनाने की कोशिश करने की संभावना उभरी थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 मई। विजय की तमिलगा वेत्री कज़गम (टीवीके) ने चेतावनी दी है कि अगर दो द्रविड़ीय पार्टियों में से कोई भी, एम.के. स्टालिन की द्रमुक (टीएमके) या ई. पलानीस्वामी की अन्नाद्रमुक तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश करने की कोशिश करता है, तो पार्टी के सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे।

यह निर्णय द्रमुक और अन्नाद्रमुक शिविरों में हुई दो महत्वपूर्ण बैठकों के तुरंत बाद आया। टीवीके को संदेह है कि दोनों पार्टियाँ राज्य में सरकार बनाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं, जिससे वह पार्टी बाहर हो जाए, जिसने जनमत में सबसे अधिक वोट पाए।

टीवीके, जिसने 107 सीटें जीतीं, का कहना है कि अकेली सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, राज्यपाल को उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।

- दोनों द्रविड़ दलों के साथ आने की संभावना इसलिए उभरी थी, क्योंकि डीएमके के युवा नेताओ को भय है कि अगर विजय मुख्यमंत्री बन गए तो वे दूसरे एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) साबित होंगे, जिन्होंने एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने जीते जी डीएमके को सत्ता के पास भी नहीं फटकने दिया।

लेकिन आज सुबह, राज्यपाल आर.वी. अरलेकर ने विजय को सरकार बनाने का दावा पेश करने की अनुमति नहीं दी, यह कहते हुए कि उनके पास आवश्यक संख्या नहीं है। उन्होंने वह योजना भी स्वीकार नहीं की, जो विजय ने बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए प्रस्तुत की थी। सूत्रों के अनुसार, यह बैठक - दो दिनों में दूसरी, राज्यपाल ने इस शर्त पर समाप्त की कि अभिनेता-राजनेता को 118 विधायकों से समर्थन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

राज भवन की एक सूचना में कहा गया कि राज्यपाल ने "तमिलनाडु विधान सभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत समर्थन स्थापित नहीं होने" की बात समझाई।

टीवीके को बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए 10 और सीटों की जरूरत है और उसके पास पहले से ही कांग्रेस का समर्थन है, जिसके पांच विधायक हैं। शेष सीटों के लिए लेफ्ट और कुछ छोटी पार्टियों के साथ बातचीत जारी है। सूत्रों ने बताया कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आज 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत

जयपुर, 8 मई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को साल 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर पीठ में एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा सुबह 8.30 बजे करेंगे। प्राधिकरण के

- मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा शुभारंभ करेंगे।

सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्रि ने बताया कि हाईकोर्ट सहित, सभी अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत के तहत कुल 479 बैंचों का गठन किया गया है, जिनमें कुल 7.77 लाख से अधिक मुकदमों को सूचीबद्ध किया गया है। लोक अदालत में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

विजय आज शपथ लेंगे तमिलनाडु के मु.मंत्री पद की

अन्ततोगत्वा तमिलनाडु के राज्यपाल को स्वीकार करना पड़ा कि उनकी ज़िद बेबुनियाद थी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 मई। कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई के समर्थन के साथ बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए, टीवीके प्रमुख विजय ने आज शाम तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अरलेकर ने लंबे समय तक चली अटकलों, अफवाहों और अनिश्चितता को समाप्त करते हुए उन्हें कल सुबह 11 बजे शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है।

इस घटना कुछ ही घंटे पहले जब लेफ्ट पार्टियों ने टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। विजय की पार्टी, जिसने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतीं, पहले सीपीआई, सीपीएम और वीसीके, जो सभी द्रमुक की सहयोगी हैं, से सरकार बनाने के लिए समर्थन मांग चुकी थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, टीवीके को आईयूएमएल को का समर्थन भी प्राप्त हुआ है, जिससे गठबंधन का बहुमत 120 सीटों तक पहुँच गया।

- शुक्रवार को राज्यपाल के साथ तीसरी मुलाकात में विजय ने कांग्रेस के अलावा वीसीके, दोनों वामपंथी दलों (सीपीआई और सीपीआईएम) और आईयूएमएल के समर्थन का प्रमाण पेश किया, जिसके बाद राज्यपाल को उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण देना ही पड़ा।
- तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके के 107 विधायक हैं, उसे कांग्रेस के 5, वीसीके के दो, सीपीआई के दो, सीपीआईएम के दो व आईयूएमएल के दो विधायकों का भी समर्थन मिल गया है, इस प्रकार विजय के पास 120 विधायकों का समर्थन है।
- विजय को सबसे बड़ी सफलता तब मिली, जब वीसीके ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा की और इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीसीके प्रमुख को मनाया था।

सप्ताह में राज्यपाल के साथ विजय की यह तीसरी मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल के पास अब विजय के दावे को खारिज करने का कोई बहाना नहीं बचा।

टीवीके के एक सूत्र ने बताया कि बैठक के दौरान विजय ने सरकार बनाने के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

संख्या बल अब विजय के पक्ष में है। टीवीके के पास 234-सदस्यीय विधानसभा में 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने पांच विधायकों के साथ समर्थन दिया है। सीपीआई और सीपीएम, जिनके दो-दो विधायक हैं, ने भी आंतरिक बैठकों के बाद टीवीके का समर्थन किया। विदुथलई चिरुथाइगल काच्ची (वीसीके), जिसके पास दो विधायक हैं, ने भी विजय का समर्थन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

टीवीके को कांग्रेस का समर्थन अवसरवादी राजनीति - मणिशंकर अय्यर

नई दिल्ली, 08 मई। पूर्व केन्द्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के साथ गठबंधन करने के कांग्रेस के फैसले को शुक्रवार को अवसरवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा की राजनीति तथा महात्मा गांधी की 1925 के उस कथन का अक्षम्य उल्लंघन है कि स्वराज का मतलब नैतिकता पर आधारित सरकार होना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहा कि कांग्रेस ने टीवीके के विजय को अपने साथ जोड़कर अनैतिक कृत्य किया है।

- पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने इसे अनैतिक कृत्य बताया।

मणिशंकर ने कहा, द्रमुक के साथ चुनाव लड़ने के तुरंत बाद उस टीवीके के साथ गठजोड़ करने का फैसला बहुत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कनिमोई ने संसद में डीएमके सांसदों के लिए अलग स्थान मांगा

यह अनायास लिया गया निर्णय नहीं है, इसका सबसे मुख्य कारण है, द्रमुक यह नहीं दिखाना चाहती कि उसने कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए हैं, इसलिए कांग्रेस के टीवीके को समर्थन देने पर वह इस प्रकार विरोध जता रही है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 मई। द्रमुक नेता कनिमोई ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर, द्रमुक सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की। उनकी पार्टी अब कांग्रेस से अलग हो चुकी राजनीतिक गलियारों में इसे केवल संसदीय व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि कहीं अधिक गंभीर राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

इसका अर्थ 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में गहरी राजनीतिक और वैचारिक दूरी के सार्वजनिक संकेत के रूप में लगाया जा रहा है।

यह घटना तमिलनाडु में राजनीतिक समीकरणों में तेजी हुए से बदलाव के बीच आई है, जहां अभिनेता-राजनेता विजय के उभरने के साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकता के भविष्य को लेकर बढ़ती अनिश्चितता देखी जा रही है।

कई वर्षों तक द्रमुक और कांग्रेस मिलकर तमिलनाडु में प्रमुख एंटी भाजपा धुरी का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। उनका गठजोड़ अक्सर धर्मनिरपेक्ष विपक्षी राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। हालांकि, संसद में अलग बैठने की मांग अब प्रतीकात्मक रूप से उस सहजता में कमी को दर्शाती है।

- कनिमोई ने जिस तरह से यह फैसला लिया है, वह पार्टी में उनके बढ़ते प्रभाव का संकेत है। डीएमके में यही व्यवस्था रही है कि स्टालिन राज्य संभालेंगे और कनिमोई दिल्ली में पार्टी को नेतृत्व देंगी।
- अब चूंकि स्टालिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, इसलिए कनिमोई का प्रभाव बढ़ रहा है।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह कदम द्रमुक की बढ़ती चिंता को दर्शाता है, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद तमिलनाडु में नए राजनीतिक समीकरण तलाश रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता राज्य में नए क्षेत्रीय दलों के उभरने और मतदाताओं की बदलती आकांक्षाओं के बीच द्रमुक पर अपनी दीर्घकालिक निर्भरता का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं।

संसद में अलग बैठने की मांग को इस बात का संकेत भी माना जा रहा है कि द्रमुक संसद में अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करना चाहती है, विशेष रूप से संघवाद, भाषा राजनीति और प्रस्तावित सीमा-निर्धारण प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर, जहां पार्टी ने दक्षिणी राज्यों पर केन्द्रित आक्रामक रुख अपनाया है।

दिलचस्प बात यह है कि इस कदम से पहले ही आम चुनावों के बाद कई क्षेत्रीय मतभेदों का सामना कर चुके इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर भी सवाल उठता है। कई विपक्षी पार्टियां निजी तौर पर डरती हैं कि राज्यों में राजनीतिक मजबूरियां अंततः राष्ट्रीय विपक्षी एकता को प्रभावित कर सकती हैं। द्रमुक के भीतर भी यह घटना कनिमोई द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय राजनीतिक संदेशों को आकार देने में निभाई जा रही बढ़ती संसदीय भूमिका को उजागर करती है। जहाँ मुख्यमंत्री एम के स्टालिन तमिलनाडु में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कनिमोई दिल्ली में पार्टी की प्रमुख राजनीतिक आवाज़ों में से एक के रूप में उभर रही हैं।

सतही स्तर पर यह केवल बैठने की एक साधारण पुनर्व्यवस्था दिखाई दे सकती है, लेकिन यह राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन की शुरुआत हो सकती है।

ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल से 'मुख्यमंत्री' नहीं हटाया

कोलकाता, 08 मई। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर राजनीतिक बहस के केन्द्र में आ गई हैं। इस समय वे मुख्यमंत्री पद पर नहीं हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अब भी उनकी पहचान मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज है। इसे लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है।

- लोग इसमें ममता का राजनीतिक संदेश देख रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में ममता बनर्जी के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मुख्यमंत्री शब्द बने रहना केवल तकनीकी चूक नहीं, बल्कि एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीकर के जाजोद में सड़कों पर घूम-घूमकर लोगों से मिले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पी और यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया

सीकर/जयपुर। सीकर के जाजोद गांव में गुरुवार को देर तक रात्रि चौपाल लगाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को सूरज निकलते ही फिर लोगों के बीच पहुंच गए। लोग घरों से निकले तो उन्होंने सड़क पर मुख्यमंत्री को गांव में टहलते हुए पाया। गांव की गलियों में सहजता के साथ भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों, पशुपालकों, फल एवं सब्जी विक्रेताओं तथा युवाओं से संवाद किया और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गांव में स्थित श्री गोपीनाथ जी मंदिर एवं शिव मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को दुलारते हुए उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानकारी ली तथा उन्हें चॉकलेट वितरित की।

सीकर के जाजोद गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घरों में जाकर लोगों से मुलाकात की।

■ गांव की गलियों में भ्रमण करते हुये सीएम ने बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों, पशु पालकों, सब्जी विक्रेताओं, युवाओं से संवाद किया

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पी और यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव का जीवन प्रकृति के निकट, शुद्धता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि शहरों की ओर पलायन की परिपाटी बदले और गांव आत्मनिर्भर विकास के सशक्त केंद्र बनें। मुख्यमंत्री ने किसानों से स्थानीय फसलों, कृषि उत्पादों एवं खेती की पारंपरिक पद्धितयों के बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें आधुनिक एवं उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीणों के अभाव अभियोगों को गंभीरता से सुनते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष बल देते हुए कहा कि आमजन को राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं एवं मांगों पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित निर्णय लेते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए। एक वीरांगना की भावनात्मक अपील पर मुख्यमंत्री ने मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए उनके भीलवाड़ा में कार्यरत पुत्र को सीकर एवं झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पलसाना (सीकर) में निरीक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति देने के आदेश भी तत्काल प्रभाव से जारी करवाए। मुख्यमंत्री ने यमुना जल समझौते को प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह समझौता भविष्य में जल संकट के समाधान तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार में मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है तथा राज्य सरकार विरासत संरक्षण के लिए हवेलियों के जीर्णोद्धार एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीण खासे उत्साहित दिखाई दिए।

ग्रामीणों ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने गांव में रात्रि विश्राम कर आमजन के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को निकटता से समझने और समाधान के प्रयास किए हैं। इस अवसर पर विधायक सुभाष मील और गोरधन वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

चिंकारा शिकार प्रकरण में दो आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर, (नि.सं.)। जिले में आर्मी फील्ड फायरिंग रेंज पोकरण में मार्च 2026 तथा फरवरी 2024 में घटित चिंकारा शिकार प्रकरण में संभागीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर अनूप के आर तथा उप वन संरक्षक जैसलमेर कुमार शुभम के मार्गदर्शन में सहायक वन संरक्षक पोकरण चंद्रशेखर कौशिक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी छायण लक्ष्मण स्वामी के नेतृत्व में गठित वन विभाग की विशेष टीम ने उक्त चिंकारा शिकार प्रकरण में दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

उपवन संरक्षक कुमार शुभम ने बताया कि फील्ड फायरिंग रेज पोकरण में फरवरी 2024 में हुए चिंकारा शिकार प्रकरण में आरोपी राहुल उर्फ रावलराम भील निवासी रामदेवरा एवं मार्च 2026 में फील्ड फायरिंग रेंज पोकरण में घटित चिकारा शिकार प्रकरण में आरोपी डालाराम भील निवासी पोकरण को वन विभाग द्वारा गिरफ्तार कर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण के समक्ष पेश करने पर दोनो आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। चिंकारा शिकार के उक्त प्रकरणों में फरार अन्य आरोपियों की तलाश कर गिरफ्तार करने के लिए वन विभाग की टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रकरणों में वन्य जीव अपराधियों को गिरफ्तार करने में रेज छायण के वनपाल झमकु, सहायक वनपाल जगदीश मेहडू वनरक्षक रामकिशोर जाखड़, अशोक रतनू, कविता स्वामी, मूलसिंह जोधा, मोहम्मद रमजान सहित अन्य वन कार्मिकों का विशेष योगदान रहा।

खेतड़ी : मकानों में चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

■ आरोपी से दो लाख रूपए का सामान व 90 हजार रूपए बरामद किये

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी पुलिस ने कस्बे में लगातार हो रही चोरियों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 90 हजार रूपए बरामद किए हैं।

थानाधिकारी मोहनलाल ने बताया कि 12 जनवरी को कस्बे के वार्ड 19 निवासी शीला पांडे ने रिपोर्ट दी कि वह 11 जनवरी को सुबह साढ़े आठ बजे घर के ताला लगाकर जयपुर गई थी। शाम के समय करीब सात बजे घर पर वापस आई और मेन गेट का ताला खोलकर मकान में आकर उपर गई तब देखा दोनों कमरों के ताले टूटे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे टूटे हुए थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने बैड में रखे नकद रुपये व अलमारी में रखे जेवरात चोरी कर लिये तथा कमरों में तोड़फोड़ कर डीवीआर भी चोरी कर ले गया। कस्बे में लगातार हो रही चोरियों को लेकर एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने थानाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया तथा पुलिस टीम में पूर्व में खेतड़ी थाने में रहे कांस्टेबल राजवीर सिंह व एचसी चौखाराम को शामिल किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता से आरोपी सोमवीर ऊर्फ मोटू पुत्र रोहिताश्व कुमावत निवासी वार्ड 18 चेलापुरी खेतड़ी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब दो लाख रूपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात व 90 हजार रूपये नकदी, चोरी किये गये रूपए से खरीदा हुआ कीमती मोबाइल फोन बरामद किया है। थानाधिकारी ने बताया कि चोरी की आरोपी के गहनता से पूछताछ की जा रही है। वारदात का खुलासा करने में डीएसटी टीम के कांस्टेबल राजवीर सिंह व एचसी चौखाराम की विशेष भूमिका रही। इस दौरान टीम में थानाधिकारी मोहनलाल, एचसी महेश, पवन कुमार, चौखाराम, कांस्टेबल राजवीर सिंह, अनिल कुमार आदि शामिल रहे।

Rajasthan Medical Services Corporation Ltd.
Gandhi Block, SwasthyaBhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005 (Raj.)
Phone No: 0141-2228066, 2228064, Website: http://rmsc.health.rajasthan.gov.in
E-mail :edpssrmsc@rajasthan.gov.in
No. :- F-8 () RMSC/EPM/M-4/NIB-933/2025-26/RajKaj 22054142 Dated :- 07/05/2026
Corrigendum / Addendum
Corrigendum / Addendum Bid No. (NIB-933) for Item White Sharp Container (White Box) for revised technical specifications has been issued. Corrigendum / Addendum details may be visited on Procurement portal website https://sppp.rajasthan.gov.in or www.dipronline.org or https://eproc.rajasthan.gov.in or website http://rmsc.health.rajasthan.gov.in.
UBN : MSC2526GLOB00056
Executive Director (EPM) RMSCL
Raj.Samwad/C/26/2396

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, WATERSHED DEVELOPMENT & SOIL CONSERVATION, PANCHAYAT SAMITI, BARI (DISTT. DHOLPUR)
File no. 101 **NOTICE INVITING BID** Date: 05.05.2026
NIT NO 03/2026-27
NIB No. WSC2627A0181 YEAR 026-27
Bids for Construction of Percolation tank with safety wall-03 in PMKSY 2.0 Project area Block Bari Distt Dholpur total estimated value INR 23.88 lacs are invited from interested bidders up to time 06:00 PM Date 15-05-2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https://eproc.rajasthan.gov.in or https://sppp.rajasthan.gov.in/)
UBN: WSC2627WSOB00299
(Prem Prakash Marmit)
EXECUTIVE ENGINEER
WATERSHED DEVELOMENT & SOIL CONSERVATION
P.S. BARI (DISTT DHOLPUR)
DIPR/C/8040/2026

OFFICE OF PROJECT MANAGER CUM SUPERINTENDING ENGINEER WATERSHED DEVELOPMENT & SOIL CONSERVATION, DHOLPUR
File no. 240 **NOTICE INVITING BID** Date: 05-05-2026
NIT NO: 01/2026-27
NIB No. WSC2627A0183 YEAR 2026-27
Bids for Construction of Retaining wall-3, Talab renovation-6, Anicut renovation-1, Ped-2 (01 Package) of total estimated value INR 121.21 lacs under PMKSY 2.0 Block Baseri Distt. Dholpur are invited from interested bidders up to time 06:00 PM Date 15-05-2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https://eproc.rajasthan.gov.in or https://sppp.rajasthan.gov.in/)
UBN:- WSC2627WSOB00301
(Lakhan singh Meena)
SE CUM PROJECT MANAGER
WATERSHED DEVELOPMENT & SOIL CONSERVATION DHOLPUR
DIPR/C/8064/2026

अलवर : गोविंदगढ़ थाने पर पथराव के चार आरोपियों को जेल भेजा

■ गोविंदगढ़ थाने पर छह मई की रात को बुलेट बाइक जब्त करने पर आरोपियों ने हमला किया था

अलवर, (निसं)। अलवर में थानेदार सहित पुलिसकर्मियों पर पथराव करने वाले चार आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 21 मई तक जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार जिले के गोविंदगढ़ थाने पर छह मई की रात को बुलेट बाइक जब्त करने पर आरोपियों ने थाने पर हमला किया था। इस हमले में गोविंदगढ़ थाना प्रभारी सहित कई कर्मचारी घायल हुए थे।

एससी/एसटी कोर्ट के सहायक लोक अभियोजक अधिकारी योगेंद्र खटाना ने बताया कि 7 मई को गोविंदगढ़ थाने के एएसआई बलबीर जाटव की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। छह मई की रात करीब 10:15 बजे एक बुलेट मोटरसाइकिल पटाखे जैसी आवाज करते हुए गुजर रही थी। योगेंद्र खटाना ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान डिटेन (जब्त) कर लिया। इसी दौरान बाइक चालक के समर्थन में 50-60 लोग थाने पहुंच गए और अचानक पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में थाने के सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और थानाधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान विक्रम सिंह, सुखजीत सिंह, अर्जुन सिंह और रौनकी सिंह के रूप में हुई है, जो सभी गोविंदगढ़ के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

युवक की मौत

कोटा, (निसं)। अनंतपुरा थाना इलाके में गलत दिशा से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक सवार काम खत्म करके घर की ओर जा रहा था कि इसी दौरान एक ट्रक रॉंग साईड से भामाशाह मंडी की तरफ से सीएनजी पम्प की तरफ जाते समय ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल बाइक सवार को उपचार के लिये अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अनंतपुरा थानाधिकारी रमेश कविया ने बताया कि बरड़ा बस्ती निवासी सोनू महावर (22) ड्यूटी से घर की ओर मोटरसाइकिल से जा रहा था, कि अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी।

टोंक में पांच लाख की अवैध शराब जब्त

टोंक, (निसं)। जिला स्पेशल टीम द्वारा दूनी थाना क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए करीब पांच लाख रुपए की अवैध शराब जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से खरीद-फरोख्त के पांच लाख 24400 रुपए रुपए भी जब्त किए हैं।

जानकारी के अनुसार दूनी थाना क्षेत्र में जिला स्पेशल टीम ने एक दुकान में छापा मारकर दुकान से 45 पेटी अवैध शराब व बोलेरो कार, नगदी आदि माल को दूनी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। टीम ने इस दौरान कार्रवाई कर गुरुवार रात्रि को दूनी थाना क्षेत्र में स्थित एनएच-52 पर संथली के पास एक दुकान पर छापामार वहां खड़ी बोलेरो गाड़ी से 15 पेटी अंग्रेजी शराब, साथ ही चालक की दुकान से 30 पेटी अंग्रेजी व देसी शराब जब्त की है। इस प्रकार आरोपियों के कब्जे से 45 पेटी अवैध अंग्रेजी व देशी शराब की जब्त की गई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग पांच लाख रुपए है। कार्रवाई में आरोपी सुरेश पुत्र देवकरण गुर्जर निवासी संथली और सांवरलाल पुत्र गोवर्धन गुर्जर निवासी बेनपा थाना दूनी को डिटेन कर दूनी थाने के सुपुर्द कर दिया है।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड मालपुरा
क्रमांकः 193 दिनांकः 6/5/2026
निविदा सूचना संख्याः 01 / 2026-27 खण्ड मालपुरा
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड मालपुरा में सडक/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के "ए" एवं "एए", "बी", "सी", "डी" श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यो हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण बेवसाईट साईट www.dipronline.org व www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN No.:- PWD2627A0347
1. PWD2627WSRC01530, 2. PWD2627WSRC01531, 3. PWD2627WSRC01532
4. PWD2627WSRC01533, 5. PWD2627WSRC01536, 6. PWD2627WSRC01537
7. PWD2627WSRC01539, 8. PWD2627WSRC01542, 9. PWD2627WSRC01547
DIPR/C/8087/2026 अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड मालपुरा

जोधपुर में शादी समारोह के स्टेज पर आग लगी, वीडियो वायरल

■ वरमाला के दौरान दूल्हा-दुल्हन ने भागकर जान बचाई

जोधपुर, (कासं)। शहर में एक शादी समारोह के दौरान वरमाला के ठीक समय स्टेज धूं-धूं कर जल उठा। पाल रोड स्थित रिसॉर्ट में हुई इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि दूल्हा-दुल्हन और वहां मौजूद लोगों ने समय रहते सूझबूझ दिखाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।

वायरल वीडियो के अनुसार स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन वरमाला की रस्म के लिए खड़े थे। इस पल को और शानदार बनाने के लिए स्टेज के चारों तरफ कोल्ड फायर (क्रैकर) चलाए गए और भारी आतिशबाजी की गई। तभी कोल्ड फायर से निकली चिंगारी स्टेज पर सजावट के लिए लगाए गए आर्टिफिशियल (प्लास्टिक) फूलों और कपड़ों पर जा गिरी। इस पर प्लास्टिक के फूलों ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते ही देखते चंद सेकंड में पूरा स्टेज आग की लपटों से घिर गया। जैसे ही स्टेज पर आग भड़की, वहां मौजूद मेहमानों और रिश्तेदारों में चीख-पुकार मच गई। आग की लपटों को अपने करीब आता देख दूल्हा और दुल्हन ने तुरंत स्टेज से नीचे की तरफ भागकर अपनी जान बचाई। अचानक लगी इस आग से मैरिज गार्डन में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि, वहां मौजूद लोगों ने अग्निशमन उपकरणों व पानी की मदद से आग पर काबू पा लिया।

प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक के लिए प्रवेश 13 मई से

■ जेईई मेन्स वालों को पहले मौका, ऑनलाइन रिपोर्टिंग से घर बैठे ही सीट कन्फर्म होगी

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश के सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक प्रथम वर्ष सत्र 2026-27 के प्रवेश 13 मई से शुरू होंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर (ईसीबी) सहित राज्य के सभी इंजीनियरिंग संस्थानों में इस वर्ष भी प्रवेश केंद्रीकृत, ऑनलाइन और मेरिट आधारित प्रक्रिया के तहत होंगे। इससे विद्यार्थियों को पारदर्शी तरीके से पसंदीदा कॉलेज और ब्रांच में प्रवेश का अवसर मिलेगा। ईसीबी में आठ ब्रांचों में करीब 600 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे, जबकि यूसीईटी में लगभग 480 सीटें उपलब्ध रहेंगी।

ईसीबी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नवीन शर्मा ने बताया कि सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जयपुर द्वारा संचालित यह प्रक्रिया विद्यार्थियों को सरल और तकनीक आधारित प्रवेश सुविधा प्रदान करेगी। प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध करवाई गई है। 13 मई से शुरू होने वाली आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को जीएसटी समेत 885 रुपए जमा करवाकर ओटीपी आधारित ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 10 जून निर्धारित की गई है, जबकि आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 जून रहेगी। अभ्यर्थी 26 जून तक कॉलेज और ब्रांच विकल्प भरकर लॉक कर सकेंगे।

प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 12वीं में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है। साथ ही अभ्यर्थियों ने विज्ञान वर्ग में गणित, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बिजनेस स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी या एंटरप्रेन्योरशिप जैसे विषयों के संयोजन के साथ अध्ययन किया होना चाहिए।

डॉ. संजीव जैन, प्राचार्य, ईसीबा का कहना है प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की सहायता के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में विशेष हेल्पडेस्क शुरू की गई है। यहां विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन, ब्रांच चयन, पात्रता, काउंसलिंग प्रक्रिया, तकनीकी पाठ्यक्रमों और करियर संभावनाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।

Estate Officer
Rajasthan University of Veterinary and Animal Science (Jobner)
क्रमांक :- EO/RUVAS/2026-27/35 दिनांक :- 05/05/2026
ई-निविदा सूचना संख्या 02/2026-27
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर की ओर से विश्वविद्यालय में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में, इस विश्वविद्यालय में एवं अन्य विश्वविद्यालयों में, राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों तथा केन्द्र सरकार व केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों, जो कि राज्य सरकार के उपयुक्त श्रेणी के समकक्ष हो, पंजीकृत संवेदकों से ई-टेन्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाईन निविदा प्राप्त की जावेगी। निविदा से संबंधित विरण वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in/tenders.asp, www.ruvasjaipur.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in व www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निविदा आवेदन डाउनलोड़ करने की तारीख	05.05.2026 सांय 5.00 बजे से
निविदा जमा कराने की तारीख	29.05.2026 सांय 5.00 बजे तक
निविदा खोलने की तारीख	30.05.2026 प्रातः 11.00 बजे से

UBN No. : RVJ2627WSOB00004
राज.संवाद/सी/26/2382 सम्पदा अधिकारी

संपत्ति के फर्जी दस्तावेज दिखाकर 12 लाख की ठगी

अजमेर, (निसं)। अलवर गेट थाना क्षेत्र में संपत्ति के फर्जी दस्तावेज दिखाकर 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोपी युवक पर विश्वास में लेकर नकली कागजात के आधार पर रकम हड़पने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अलवर गेट थाना क्षेत्र स्थित सेंट जोसेफ स्कूल आनंदपुरी निवासी नवल सिंह ने अलवर गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि एक युवक ने उसे संपत्ति बेचने का झांसा दिया। आरोपी ने खुद को संपत्ति का मालिक बताते हुए संबंधित जमीन और मकान के दस्तावेज दिखाए। दस्तावेज देखने के बाद नवल सिंह ने उस पर भरोसा कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने संपत्ति का सौदा तय कर उससे अलग-अलग किश्तों में करीब 12 लाख रुपए ले लिए। बाद में जब दस्तावेजों की जांच करवाई गई तो वे फर्जी निकले। इसके बाद पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का पता चला।

अलवर गेट थाना एएसआई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दस्तावेजों की सत्यता की भी जांच करवाई जा रही है तथा आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

पावटा : लग्न-टीका कार्यक्रम में रस मलाई खाने से करीब 50 लोगों की तबियत बिगड़ी

बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई

पावटा, (निसं)। भाभरु क्षेत्र के मालियों की ढाणी, गैसकान में शुक्रवार को दोपहर में आयोजित एक लग्न-टीका कार्यक्रम उस समय अफरा-तफरी में बदल गया, जब भोजन के साथ मिठाई के नाम पर परोसी गई रस मलाई खाने के बाद अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी, जिससे समारोह स्थल पर हड़कंप मच गया। स्थिति गंभीर होने पर परिजनों ने तुरंत मरीजों को आंतेला सीएचसी और बाद में शाहपुरा राजकीय उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां एक साथ बड़ी संख्या में मरीज आने से अस्पताल के वार्ड भर गए।

■ भाभरु क्षेत्र के मालियों की ढाणी, गैसकान में लग्न-टीका कार्यक्रम में भोजन के साथ मिठाई के नाम पर परोसी गई थी रस मलाई

लोगों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर चिकित्सकों ने उपचार शुरु किया।

जानकारी के अनुसार करीब 50 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग की चपेट में आए हैं। हालांकि चिकित्सकों की तत्परता से सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा युवा नेता उपेन यादव देर रात शाहपुरा अस्पताल पहुंचे और मरीजों व उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों का हालचाल जाना और परिजनों को ढांढस बंधाते हुए भरोसा दिलाया कि इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। यादव ने अस्पताल के पीएमओ डॉ. विनोद योगी एवं चिकित्सा स्टाफ से चर्चा कर सभी मरीजों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। वे करीब दो घंटे तक अस्पताल में मौजूद रहकर मरीजों की स्थिति की जानकारी लेते रहे।

अस्पताल प्रशासन ने भी अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए इमरजेंसी व्यवस्था मजबूत की। मरीजों के परिजनों ने चिकित्सा टीम और सहयोग में जुटे लोगों की सराहना करते हुए राहत जताई कि समय रहते उपचार मिलने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं क्षेत्रवासियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी परेशानी में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेने की अपील की गई है। वहीं असपताल में आये लोगों को चिकित्सकों ने भर्ती कर उपचार शुरु किया।

नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। नाबालिग से छेड़छाड़ के करीब दो साल पुराने मामले में पॉस्को क्रम-3 न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक महेश चांदवानी ने बताया कि 25 मार्च 2024 को नाबालिग 15 वर्षीय पीड़िता ने शहर के एक थाने में रिपोर्ट दी। पीड़िता ने रिपोर्ट में कहा कि घर से सब्जी लेने गई थी, सब्जी की दुकान बंद होने पर पैदल घर की ओर आ रही थी। रास्ते में एक परिचित बाइक लेकर मिला जिसने बाइक से घर छोड़ने के लिये कहा और उसको बाइक पर बैठा लिया। रिपोर्ट में कहा कि वह उसे उसके घर की जगह अपने घर पर ले गया, जहां गलत हरकत करते हुए छेड़छाड़ करने लगा। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया, मामले में 10 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये।

■ पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर 10 गवाहों के बयान दर्ज कराये

कार्यालय नगर परिषद्, झुन्झुनू (राज.)
क्रमांक :-स्टोर/2026-27/1833 दिनांक :- 07.05.2026
निविदा सूचना संख्या 01/2026-2027
(NIB Code- DLB2627A1474)
कुल राशि - 12.80 लाख
नगर परिषद झुन्झुनूं की और से कार्य हेतु सक्षम श्रेणी के पंजीकृत संवेदको से मोहरबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 15.05.2026 दोपहर 1.00 बजे तक निविदा शुल्क जमा करवाकर इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। पूर्णतया भरी हुई निविदाए दिनांक 15.05.2026 को सांय 2.00 बजे तक वापिस प्राप्त की जाकर उसी तिथि को सांय 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। उक्त निविदा के सम्बन्ध में अधिक जानकारी राजस्थान लोक उपापन पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) देखी जा सकती है। कार्य दिवस में कार्यालय मे भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
आयुक्त
नगरपरिषद्, झुन्झुनूं
राज.संवाद/सी/26/2358

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
Corporate Identification Number (CIN) – U40109RJ2000SGC016482
Registerd Office : Vidyut Bhawan, Panchsheel Nagar, Makarwali Road, Ajmer-305004
Office of The Superintending Engineer (Civil)
Email-secivilavvnl@gmail.com ; http://energy.rajasthan.gov.in/avvnl
No. : AVVNL/SE/CIVIL/AJM/FC: D : 217 Date :- 04/05/2026
निविदा सूचना संख्या 01 (2026-27)
केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों में 'ए' व 'एए' श्रेणी तथा अ.वि.वि.नि.लि. के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत, अनुभवी तथा माल एवं सेवाकर विभाग से पंजीकृत निविदाकारों से अधिशाषी अभियंता (सिविल/सिविल-QC), अजमेर/उदयपुर/सीकर/चितौड़गढ़ के अधीन सिविल कार्यों के लिए निविदाऐं UBN No. AVV2627WSOB00005 to AVV2627WSOB00008 आमन्त्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धित समस्त विवरणए वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in व http://energy.rajasthan.gov.in/avvnl पर उपलब्ध है।
राज.संवाद/सी/26/2363 अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
क्रमांक :- लेखा/भ.वि.प्रा./2026-27/5387 - 98 दिनांक :- 05/05/2026
ऑनलाईन निविदा सूचना सं. 09/2026-27
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से कुल 02 कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
उक्त कार्यो का विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते, अनुमानित लागत राशि, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेवसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in https://bhda.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in portal पर देखा जा सकता है।
निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in portal का अवलोकन करें।
UBN विवरणः- WAQ2627WSOB00033, WAQ2627WSOB00034
राज.संवाद/सी/26/2373 अधिशाषी अभियन्ता

कोटा में दो प्रसुताओं की मौत के मामले में कांग्रेस ने धरना दिया

कोटा में प्रसुताओं की मौत के मामले में कांग्रेस ने धरना दिया।

■ सरकार सो रही है और विधायक, प्रधानाचार्य खिलखिला रहे हैं, माताएं दम तोड़ रहीं हैं : राखी गौतम

कोटा, (निसं)। मेडिकल कॉलेज कोटा में विगत दिनों से प्रसूताओं के जीवन के साथ हो रहे खिलवाड़ और अस्पताल प्रशासन की आपराधिक लापरवाही से दो प्रसूताओं की मौत के मामले में को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राखी गौतम, भानूप्रताप की अगुवाई में कांग्रेस जनों ने 8 मई शुक्रवार मेडिकल कॉलेज के सामने दोपहर 3.30 बजे धरना देकर सरकार को घेरते हुए मेडिकल कॉलेज के बाहर उग्र प्रदर्शन कर विरोध जताया तथा सरकार की नींद जगाने के लिए 10 मुखी रावण रूपी सरकार के पुतले का दहन किया गया।

10 मुखी पुतले में एक ओर स्थानीय सांसद ओम बिरला, स्थानीय विधायक संदीप शर्मा, चिकित्सा मंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के चेहरे थे। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रधानाचार्य, अस्पताल अधीक्षक सहित पूरे अस्पताल प्रशासन के चेहरे लगाए गए। इस मौके पर धरने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए शहर अध्यक्ष राखी गौतम ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही नहीं, सीधी सीधी हत्या है।

चिकित्सा मंत्री को शायद पता ही नहीं कि वह राजस्थान सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं या फिर उनके पास अभी तक पर्ची नहीं पहुंची कि घटनास्थल पर पहुंचें। अस्पताल के प्रधानाचार्य ने एक मौत के बाद भी नही जागे और दूसरे दिन दूसरी प्रसूता की मौत का इंतजार करते रहे उसकी भी मौत हो गयी विधायक के दौरे पर विधायक और प्रधानाचार्य खिलखिलाते नजर आए इससे साफ है कि इन्हें माताओं की मौत और बच्चों के अनाथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राखी गौतम ने कहा हमने प्राचार्य के समक्ष मृतक पीड़ित मरीजों के पक्ष में पांच मांगे रखी थी पहली दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो,इस्तेमाल की गयी मेडिसिन को जब्त कर जांच की जाय, उच्चस्तरीय मजिस्ट्रेट जांच हो, मृतक के परिजन को 10 लाख का मुआवजा, लापरवाही के चलते गंभीर रूप से ग्रसित हुई महिलाओं को पांच लाख का मुआवजा मिले और उनका पूरा ईलाज फ्री हो यह मांगे रखी थी लेकिन सोई हुई सरकार और अस्पताल व जिला प्रशासन के अभी तक जूं नही रेंगी है। राखी गौतम ने कहा कि सरकार की अनदेखी और अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते मौते हुई है इसकी समस्त जिम्मेदारी मौत का तांडव देख रही राज्यसरकार की अनदेखी है इसका पुरजोर विरोध किया जायेगा। कोटा जिला प्रभारी पुष्पेन्द्र भारद्वाज ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को अभी तक आलाकमान से निर्देशित नहीं किया गया है कि कोटा प्रवास पर जाएं और मामले का संज्ञान लें। क्या भाजपा आलाकमान के आदेश के बिना कोटा की माताओं की मौत पर भी संज्ञान नहीं लेगी यह लापरवाही पूर्ण रूप से अस्पताल प्रशासन और सरकार की है। इसे किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। हमारे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कमेटी घटित कर निर्देश दिए हैं हम दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। देहात अध्यक्ष भानूप्रताप ने कहा कि हमने सरकार और अस्पताल प्रशासन को कुंभकरण की नींद में सोई हुई सरकार को जगाने के लिए बिगुल बजाय है लेकिन सरकार ने अभी तक किसी को वास्तु स्थिति को पता करने या मामले की जांच के लिए किसी को नही भेजा है यह सोचनीय गंभीर विषय हैं।

विधायक चेतन पटेल ने कहा कि दो मोते होने के बावजूद सरकार ने अभी तक किसी भी मामले में संज्ञान नही लिया क्या सरकार को ओर मोतो का इंतजार है उन्होंने कहा कि उक्त मामले में कांग्रेस चुप नही बैठेगी और उग्र आंदोलन करना पड़े पीछे नहीं हटेंगी।

लाड़पुरा प्रधान रहे नईमुद्दीन गुड्डु ने कहा कि डॉक्टर को मरीज भगवान मानते हैं उनको इनके कारनामों से पता चल रहा है कि यह मौत के सौदागर है इनके कारनामो की उच्च स्तरीय जांच कर उचित कार्यवाही होनी चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सकें। सह प्रभारी धर्मराज मेहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी चिकित्सा व्यवस्था में पूर्णतया फैल है घटना की न्यायिक जाँच होनी चाहिऐं रामगंजमंडी विधायक प्रत्याशी रहे महेन्द्र सिंह राजौरिया ने कहा कि लापरवाही के चलते प्रसूताओं की मौतें हुई है शीघ्र न्यायिक जांच होकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही एवं पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

धरने के संचालन कांग्रेस महासचिव डॉ.विजय सोनी ने किया। डॉ.विजय सोनी ने बताया धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी,पूर्व विधायक पूनम गोयल, पीसीसी सचिव शिवराज गुंजल, कैथून नगर पालिका चेयरमैन आयना महक, निवर्तमान महापौर पवन मीणा, सोनू कुरैशी, उपाध्यक्ष जगदीश ठाड़ा, राधेश्याम वर्मा, श्याम गौतम, उपाध्यक्ष अनुराग गौतम, एनएसयूआई के अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा आदि मौजूद थे।

स्कूली बच्चों में शिक्षा के साथ भक्ति भावना जगाई

श्रीराम सेवा समिति की ओर से स्कूली बच्चों को स्टेशनरी वितरित की गई।

कोटा, (निसं)। स्कूली बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार, भक्ति भावना और सकरात्मक उर्जा का संचार करने के उद्देश्य को लेकर श्रीराम सेवा समिति द्वारा सेवा कार्यक्रम के तहत आयोजित भजन कीर्तन में स्कूली बच्चों को सम्मिलित किया गया।

श्रीराम सेवा समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने बताया कि ट्रक यूनियन के समीप स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय बदला बस्ती में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिससे पूरा वातावरण श्रीराम जय राम के भजनों से भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर समिति द्वारा स्कूली बच्चों को स्टेशनरी सामग्री वितरित की गई साथ ही प्रसादी व फलों का वितरण किया गया।

श्रीराम सेवा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में समिति के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

राधा-कृष्ण मंदिर का भूमि पूजन आज

कोटा, (निसं)। गीता सत्संग आश्रम समिति, कोटा द्वारा गीता भवन स्थित प्राचीन भगवान श्री राधा-कृष्ण मंदिर के भव्य नवनिर्माण एवं श्कृष्ण लीलाश के सजीव चित्रण का भूमिपूजन एवं शिलान्यास समारोह शनिवार को प्रात: 11 बजे गीता भवन प्रांगण में आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे।

अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए के 245 मोबाइल रिकवर किये

कोटा, (निसं)। शहर पुलिस की अलग-अलग थानों की टीमों ने मोबाईल गुम होने की दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 245 मोबाईल रिकवर किए। पुलिस टीम द्वारा रिकवर किए गए मोबाईलों की कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई गई हैं। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि सीईआईआर पोर्टल व जिले के विभिन्न थानों पर विगत वर्षों में कोचिंग छात्रों से व आमजन से गुमशुदा हुए मोबाईल फोन की दर्ज रिपोर्ट में गुमशुदा मोबाईल की तलाश कर बरामदगी हेतु विशेष अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही करने हेतु दिलीप सैनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में थानास्तर पर अलग-अलग टीमें गठित कर रिकवरी के प्रयास किये गये। टीमों द्वारा कोटा शहर में राज्य व राज्य से बाहर विगत वर्षों में गुमशुदा हुए मोबाईलों का सीईआईआर पोर्टल पर से डाटा का तकनीकी विश्लेषण करके राजस्थान व राजस्थान से बाहर विभिन्न राज्यों से विभिन्न कम्पनियों के मल्टीमीडिया कीमती मोबाईल बरामद किये जाकर मोबाईल मालिकों को सुपुर्द किये गये।

शहर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामद कुल 245 मोबाईल जिनकी अनुमानित कीमत 60 लाख रुपये है। शहर पुलिस ने आमजन से अपील है कि मोबाईल चोरी/गुम होने आदि कि स्थिति में व्यक्ति स्वयं भी राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर मोबाईल की गुमशुदगी की रिपोर्ट ऑनलाईन दर्ज करवा सकता है।

अफीम डोडा-चूरा तस्कर को 3 साल की सजा

कोटा, (निसं)। अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा तस्करी के तकरीबन सात साल पुराने मामले में एनडीपीएस न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह निर्भय ने बताया कि 3 मार्च 2019 को आरकेपुरम् थानाधिकारी मय जाप्ता गश्त के दौरान गुर्जर चौक पर पहुंचकर आने-जाने वाले वाहनों व लोगों की चैकिंग कर रहे थे, उसी दौरान एक व्यक्ति हाथ में थैला लेकर कोटा यूनिर्वसिटी की तरफ से आता हुआ नजर आया। जो पुलिस जाप्ता को देखकर पीछे मुड़कर तेज कदमों से जाने लगा, जिसे पुलिस टीम ने रोका और संदेह होने पर तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थ 8 किलो 770 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती माया गुर्जर पत्नी श्री गोपाल गुर्जर, निवासी बांके बिहारी मंदिर के पास, रंगबाड़ी, कोटा (राज.) द्वारा मकान नं. 1233-बी (कॉर्नर, श्रीनाथपुरम् आवासीय योजना, कोटा (राज.) को खरीदने बाबत् करार श्रीमती संतोष पांचाल पत्नी श्री गिरिराज पांचाल, निवासी मकान नं. 1233-बी, श्रीनाथपुरम, कोटा (राज.) से किया हुआ है। उक्त मकान का क्रय श्री गिरिराज पांचाल ने श्रीमती कैलाश पांचाल पत्नी श्री प्रकाश पांचाल से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 14.10.09 से किया गया था, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा में दिनांक 14.10.09 को हो रहा है। श्री गिरिराज पांचाल का स्वर्गवास दिनांक 15.07.2020 को हो गया है। उनकी मृत्युपरान्त उनके विधिक उत्तराधिकारी श्री आकाश, श्री आशीष, श्रीमती रीतू पांचाल एवं श्रीमती संतोष पांचाल उक्त सम्पत्ति के संयुक्त रूप से स्वामी बनें। इसके पश्चात् श्री आकाश, श्री आशीष एवं श्रीमती रीतू पांचाल द्वारा अपने-अपने अविभाजित हिस्से का हक त्याग अपनी माता श्रीमती संतोष पांचाल के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 06.01.2023 से किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा में दिनांक 06.01.2023 को हो रहा है। कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा उक्त मकान का नाम हस्तांतरण भी श्रीमती संतोष पांचाल के पक्ष में जरिये कार्यालय आदेश दिनांक 25.03.2026 से किया जा चुका है। उक्त सम्पत्ति वर्तमान में कोटा नागरिक सहकारी सहकारी बैंक लि.. शाखा आर.के. पुरम, कोटा में रहन है।

अगर किसी व्यक्ति अथवा वित्तीय संस्था को उपरोक्त वर्णित अचल सपत्ति को बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटा में साम्यक् बंधक रखने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो वह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस की अवधि में मुझे अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत कर दें, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

कोटा

दिनांक: 8.5.26

राजेन्द्र मंगल एडवोकेट

मकान नंबर 322 महावीर नगर द्वितीय

कोटा राज.

मो. 94148-02953

विद्यार्थियों को टेबल-कुर्सी सेट उपलब्ध कराए

रामगंजमंडी, (निसं)। क्षेत्र के सलावद, झिरी, झीलरा और बड़ौदिया के राजकीय विद्यालयों में शुक्रवार को विद्यार्थियों को टेबल-कुर्सी सेट उपलब्ध कराए गए। शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर के जन्मदिन के उपलक्ष में वन विभाग की जनसहभागिता योजना के तहत यह पहल की गई। विद्यालयों में टेबल-कुर्सी पहुंचने पर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लंबे समय से जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को अब बेहतर सुविधा मिल सकेगी। मण्डल अध्यक्ष शांति बाई ने कहा कि चारों विद्यालयों में कुल 138 टेबल-कुर्सी सेट वितरित किए गए। इनमें सलावाद विद्यालय को 30 सेट, झिरी को 34 सेट, झीलरा को 34 सेट एवं बड़ौदिया विद्यालय को 40 सेट उपलब्ध कराए गए।

पटवार संघ ने ज्ञापन सौंपा

नैनवां (निसं)। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा नैनवां ने राजकीय अवकाश के दिनों में कर्मचारियों से कार्य करवाने का विरोध जताते हुए शुक्रवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उपशाखा अध्यक्ष परमानन्द गुर्जर के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कर्मचारियों को रविवार और अन्य सरकारी छुट्टियों में कार्य से मुक्त रखने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि विभिन्न योजनाओं और प्रशासनिक कार्यक्रमों के चलते कर्मचारियों से लगातार अवकाश के दिनों में भी ड्यूटी ली जा रही है। इससे कर्मचारियों के पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। संघ ने कहा कि लगातार बढ़ते कार्यभार से कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो रही है। पटवार संघ ने मांग की कि अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश के दिनों में कर्मचारियों से कार्य नहीं लिया जाए।

कार चोरी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

कोटा, (निसं)। कार चोरी के दर्ज मामले में कुन्हाड़ी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 3 मई को फरियादी ने कुन्हाड़ी थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि 1 मई को सुबह मेरे बेटे का स्कूल के लिय छोड़ने के लिय निकला तो मेरी क्रेटा कार घर के बाहर नजर नही आई तो फिर मैने पड़ोस के सीसीटीवी कैमरा में देखा तो कार को कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया फिर मैने आस पास तलाश किया तो मेरी गाड़ी नही मिली। शहर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया।

शहर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस उप अधीक्षक डॉ.पूनम के सुपरविजन में कुन्हाड़ी थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज के नेतृत्व में टीम गठित की गई। मामले में कुन्हाड़ी व शहर की विशेष टीमों द्वारा किये गये तकनीकी अनुसंधान से पाया गया कि उक्त कार चोरी की घटना आसिफ हुसैन उर्फ आशु एव सुनिल नागर उर्फ कच्चु द्वारा की गई है, जो पूर्व में भी कोटा शहर, बून्दी, बारां में वाहन चोरी की वारदातें कर चुके है तथा शातिर प्रवृति के अपराधी है।

उक्त आरोपियों की गिरफतारी हेतु गठित टीमों द्वारा इनके संभावितों स्थानों पर तलाश प्रारम्भ कर मुखबिर मामूर किये गये, उक्त कार चोरों के सबंध में टीम को तकनीकी अनुसंधान सूचना मिली की उक्त कार चोर वर्तमान में मध्यप्रदेश के आगर जिले के बड़ौद कस्बे में छुपे हुये हैं, जिस पर टीम ने बड़ौद मध्यप्रदेश पहुंचकर उक्त चोरों को तलाश किया तो बड़ौद कब्जे में डग रोड पर एक बिना नम्बरी केटा कार खड़ी नजर आई जिसके अन्दर दो व्यक्ति भी बैठे हुए थे। जिस पर टीम ने कार के समीप पहुंचकर चोरों को डिटेन करने हेतु घेरा डाला तो कार चोरों ने कार को स्टार्ट करके भगाने का प्रयास किया। जिस पर टीम ने आरोपियों का पीछा कर दोनों आरोपियो को चोरी की कार सहित डिटेन करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आसिफ हुसैन उर्फ आशु एव सुनिल नागर उर्फ कच्चु को गिरफ्तार किया।

उक्त आरोपियों ने पूछताछ में चौपाटी छावनी थाना गुमानपुरा में महिला से छीना-झपटी कर पर्स छीनने की वारदात भी कबुल की है। जिसके संबंध में थाना गुमानपुरा पर प्रकरण दर्ज हैं।

तरीका ए वारदात-उक्त अपराधियों ने छीना झपटी की वारदात करने के उद्देश्य से प्रात: रैकी कर फरियादिया के अकेली मिलने पर मौका देखकर उससे पर्स छिनकर फरार हो गये। पर्स में मिले फरियादि की आईडी कार्ड एवं कार की चाबी से फरियादी के मकान की रैकी की तथा मौका देखकर कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

KOTA BUS SERVICES LIMITED

CIN : U60210RJ2015SGC047372, Nagar Nigam Kota, New Administrative Building, Rajeev Gandhi Bhawan, Dushera Maidan Kishorpura, Kota, 324009, E-mail :kbslcitybus@gmail.com

No. :- KBSL/NNK/2025-26/1315 - 1332 Date :- 05/05/2026

Kota Bus Services Ltd. Invites online tender from eligible placement agency/eligible registered Contractors and Clerical Work for below mentioned work. Detailed tender document can be download from website www.eproc.rajasthan.gov.in www.sppp.rajasthan.gov.in.

UBN : DLB2627WLRC03858

Raj.Samwad/C/26/2403

Chief Executive Officer

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक : एफ 7/डी.टी.पी./2026/820-25 दिनांक : 08/05/2026

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बनाये गए नियमों/प्रपत्रों के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण, भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु कोटा विकास प्राधिकरण मे विचाराधीन है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस मे कोटा विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नही किया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड सं./ योजना का नाम	योजना/मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल
1.	मैसर्स काईजन इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्री द्वारका दास नैनानी	भूखण्ड सं. 1-ए श्रीनाथपुरम-ए कोटा	स्कूल	हॉस्पिटल	1939.05 वर्गमीटर

उप नगर नियोजक कोटा विकास प्राधिकरण

ग्राम रथ अभियान में शामिल हुए शिक्षा मंत्री दिलावर

कोटा, (निसं)। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यो को ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित ग्राम रथ अभियान के तहत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी ऑडियो-वीडियो मोबाईल वैन के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अभियान के जरिए मुख्यमंत्री का संदेश भी ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें सुशासन, पारदर्शिता एवं अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

अभियान के माध्यम से प्रशासन स्वयं गांव-गांव पहुंचकर आमजन की समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य कर रहा है। ग्राम रथ अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुद्धखान, ब्लॉक खैराबाद में शुक्रवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अभियान में शामिल हुए। उन्होंने चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद कर अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दिलवाई तथा पात्र एवं वंचित लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।

उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। साथ ही, ग्रामीणों को सुझाव पेटिका में अपने सुझाव देने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि जनभागीदारी से ही योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हैं। ग्राम पंचायत अरण्डखेड़ा के ग्राम झोपड़िया में आयोजित ग्राम रथ अभियान के दौरान ग्रामीणों ने स्वयं आगे आकर योजनाओं से मिले लाभ साझा किए। अभियान के माध्यम से यह सामने आ रहा है कि सरकार की योजनाएं वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही हैं और ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

यशोदा बाई निवासी झोपड़ियां ने बताया कि वे पहले अपने परिवार सहित झोपड़ी में निवास करती थीं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत उन्हें पक्का मकान निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई। योजना के तहत उन्होंने अपना पक्का मकान बनवाया तथा आवास की तीनों किश्तें भी प्राप्त हो चुकी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना ने उनके परिवार को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया।

आम सूचना

मेरे पक्षकार उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक, झालावाड़ रोड़, कोटा की ओर से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सम्पत्ति भूखण्ड संख्या 26, नई धानमण्डी, कोटा (राज.) पैमाईशी 1800 वर्गफुट की लीज डीड हरवंश लाल एवं सुभाष चन्द्र के पक्ष में कार्यालय उप पंजीयक कोटा के यहां दिनांक 06.09.1979 को हो रहा है। तत्पश्चात हरवंश लाल एवं सुभाष चन्द्र ने उक्त भूखण्ड को पूर्वी भाग पैमाईशी 900 एवं 900 वर्गफुट का बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1987 से श्री चन्द्रप्रकाश को कर दिया तथा शेष पश्चिमी भाग पैमाईशी 900 वर्गफुट का बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1987 से श्री हरि सिंह को कर दिया। उक्त भूखण्ड के पूर्वी भाग में दुकान नम्बर 1 जिसको तरूण कुमार जोतवानी आत्मज श्री शंकरलाल जोतवानी द्वारा खरीदने का इकरार किया है और ऋण प्राप्त करने हेतु मेरे पक्षकार के यहां आवेदन किया है। उक्त दुकान के विक्रय इकरार बाबत किसी भी व्यक्ति, बैंक या संस्था या अन्य किसी को भी किसी भी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अंदर मियाद 07 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी।

दिनांक : 08.05.2026

भवदीय

राजेन्द्र सिंह एडवोकेट

386, माला रोड़, कोटा जं.

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11 विक्रय/2026/180 दिनांक : 7.5.26

नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 75-बी कॉर्नर कोटा टायर रिपेयरर्स एसोसिएशन विश्वकर्मा नगर व्यावसायिक योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 03 दिनांक 17.09.2013 को मैसर्स आदर्श टायर रिपेयरिंग प्रोद्य श्री अनवर खान पुत्र श्री रोशन खान के नाम आवंटन किया गया था। श्री अनवर खान पुत्र श्री रोशन खान द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री हरीश कुमार नागर पुत्र श्री रामदयाल नागर द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.11.2024 को श्री वंश धाकड़ पुत्र श्री हरीश कुमार नागर को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्री वंश धाकड़ पुत्र श्री हरीश कुमार नागर द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 75-बी कॉर्नर कोटा टायर रिपेयरर्स एसोसिएशन विश्वकर्मा नगर व्यावसायिक योजना का नाम हस्तान्तरण श्री वंश धाकड़ पुत्र श्री हरीश कुमार नागर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

पांच रेलकर्मियों को 'संरक्षा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र' से सम्मानित किया

कोटा मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने पांच रेल कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

कोटा, (निसं)। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में ड्यूटी के दौरान असाधारण सतर्कता, त्वरित निर्णय क्षमता एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देकर संभावित दुर्घटनाओं को टालने वाले 5 रेलकर्मियों को मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा द्वारा "संरक्षा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र" प्रदान कर सम्मानित किया गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि पुरस्कृत कर्मचारियों में स्टेशन मास्टर निर्मल कुमार, पॉइंट्समैन-ए ललित कुमार बोरासी, उप स्टेशन अधीक्षक राजेश कुमार जांगिड, ट्रेन मैनेजर विनोद कुमार मीना तथा टीआरडी टेक्नीशियन सत्यनारायण गुर्जर शामिल हैं। इन कर्मचारियों ने समय रहते तकनीकी असामान्यताओं की पहचान कर न केवल रेल संपत्ति को नुकसान से बचाया, बल्कि यात्रियों एवं रेलकर्मियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। उनकी सजगता और तत्परता से कई बड़ी घटनाएँ टल गईं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि रावथा रोड स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों ने गुजरती ट्रेन के एक कोच से आग की लपटें निकलती देखी।

कर्मचारियों ने तुरंत ट्रेन को रुकवाया, संबंधित अधिकारियों को सूचना दी तथा मौके पर पहुँचकर अग्निशमन यंत्रों की सहायता से आग पर काबू पाया। समय रहते की गई इस कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टल गई। इसी प्रकार मखौली स्टेशन पर एक रेलकर्मी ने गुजरती मालगाड़ी के पहिए से धुआँ उठता देखा। उन्होंने तत्काल सतर्कता बरतते हुए ट्रेन को रुकवाया और संबंधित स्टॉफ को सूचित किया। जांच में तकनीकी खराबी सामने आई, जिसे समय रहते ठीक कर लिया गया। इस त्वरित कार्रवाई से रेल संचालन प्रभावित होने से बच गया। गंगापुर सिटी स्टेशन पर एक कर्मचारी ने मालगाड़ी की जांच के दौरान डिब्बों के बीच कपलिंग में गंभीर असामान्यता देखी। उन्होंने तुरंत संबंधित विभाग को सूचित कर आवश्यक कार्रवाई करवाई। दोषपूर्ण हिस्से को अलग कर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया गया।

वहीं विद्युत विभाग के एक कर्मचारी ने फुट पेट्रोलिंग के दौरान ओएचई लाईन में गंभीर खराबी देखी, जिससे रेल संचालन बाधित हो सकता था। उन्होंने तत्काल अधिकारियों को सूचना देकर मरम्मत कार्य शुरू करवाया। समय पर की गई कार्रवाई से संभावित बड़ा ब्रेकडाउन टल गया और रेल संचालन सुरक्षित बना रहा।

मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने सभी पुरस्कृत कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि रेलवे में संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा ऐसे सजग एवं समर्पित कर्मचारी पूरे मंडल के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि कोटा मंडल सुरक्षित एवं विश्वसनीय रेल संचालन के लिए सदैव प्रतिबद्ध है और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को आगे भी प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।

सेवा कार्यों से जुड़े लोगों को सम्मानित किया

छबड़ा (निसं)। नगर पालिका द्वारा क़स्बे में स्वच्छता एवं सामाजिक जिम्मेदारी निमाने वाले विभिन्न दुकानदारों एवं सेवा कार्यों से जुड़े लोगों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अधिशासी अधिकारी संदीप गहलोत ने बताया कि कटिंग कार्य करने वाले, सब्जी विक्रेता, चाय विक्रेता, गन्ने के जूस विक्रेता, सार्वजनिक शौचालय की साफ-सफाई बनाए रखने वाले तथा अस्पताल एवं मेडिकल की दुकानों के आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने वाले नागरिकों को नगरपालिका द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान सफाई निरीक्षक राजेन्द्र कुमार एवं प्रतीक नागर मौजूद रहे। शहर की स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि आमजन और दुकानदारों के सहयोग से ही एक स्वच्छ एवं सुंदर शहर का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा हैं, जो अपने कार्यस्थल के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्र को भी साफ-सुथरा रखते हैं। कार्यक्रम के दौरान सभी सम्मानित व्यक्तियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की गई। नगरपालिका द्वारा भविष्य में भी स्वच्छता एवं जनजागरूकता से जुड़े कार्यों में सहयोग करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक सम्पति मकान नम्बर 744, रामकृष्ण पुरम ए, आवासीय योजना कोटा के स्वामी श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री खेमचन्द, निवासी मकान नम्बर 315, पुरानी धानमण्डी कोटा (राज.), से मेरी पक्षकारा श्रीमति भारती मेहरा पत्नि श्री चन्द्रप्रकाश मेहरा, निवासी मकान नम्बर 559, विनोबाभावे नगर, कोटा (राज.) ने उक्त मकान को क्रय करने का इकरार दिनांक 06.05.2026 को कर उक्त सम्पति पर मेरी पक्षकारा द्वारा HDFC Bank शाखा कोटडी सर्किल कोटा से आवास ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, उक्त मकान के मूल दस्तावेज जिसमें भू-आवंटन पत्र क्रमांक 253 दिनांक 04.02.1997 जो नगर विकास न्यास कोटा द्वारा विक्रेता के पक्ष में जारी किया गया है, कहीं मिस प्लेस हो गया है, उक्त सौदे से भी आम व खास को किसी प्रकार का उज्र अथवा एतराज हो, तो अन्दर 5 योम लिखित में मुझे अथवा मेरे पक्षकार को कर दे, इसके पश्चात कोई उज्र, एतराज मान्य नहीं होगा, तथा उक्त सम्पति के स्वामित्व सम्बन्धी उपरोक्त मूल दस्तावेज किसी आम व खास को मिल जावे तो मुझे अथवा मेरे पक्षकार को अथवा HDFC Bank शाखा कोटडी सर्किल कोटा को सुपुर्द कर दे, तथा उक्त दस्तावेजों का कोई मिसयूज नहीं करे। कृपया सूचित हो।

कोटा

दिनांक-08.05.2026

भवदीय

गोविन्द नामदेव एडवोकेट

मो.न. 9414284515

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11 विक्रय/2026/181 दिनांक : 8.5.26

नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 1005 सुभाष नगर आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 781 दिनांक 09.05.1991 को श्री भानु कुमार पुत्र श्री काली पत के नाम आवंटन किया गया था। श्री भानु कुमार पुत्र श्री काली पत द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री राहुल रोबर्ट पुत्र श्री रोबिन पीटर द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.09.2025 को श्री सुरेश पुत्र श्री चतुर्भुज को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्री सुरेश पुत्र श्री चतुर्भुज द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 1005 सुभाष नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री सुरेश पुत्र श्री चतुर्भुज के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विक्रय/2026/1077 दिनांक : 7.5.26

नाम हस्तातंरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-50 आर.के.पुरम. बी योजना के आवंटन के पत्र क्रमांक 72 दिनांक 08.01.2002 द्वारा श्री चन्दगीराम राव पुत्र श्री टोडाराम को आंवटित किया गया था। श्री चन्दगीराम के द्वारा मृत्यु से पूर्व रजिस्टर्ड वसियत पत्र श्री जयसिहं राव के पक्ष में वसियत पत्र निष्पादित किया गया। श्री चन्दगीराम कि मृत्यु दिनांक 06.03.2008 को चुकी है। वसियत ग्रहिता श्री जय सिहं राव पुत्र श्री चन्दगीराम ने अपने नाम उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृती देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखण्ड संख्या-50 आर.के.पुरम. बी योजना का नाम हस्तांतरण श्री जय सिहं राव पुत्र श्री चन्दगीराम के नाम कर दिया जावेगा। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

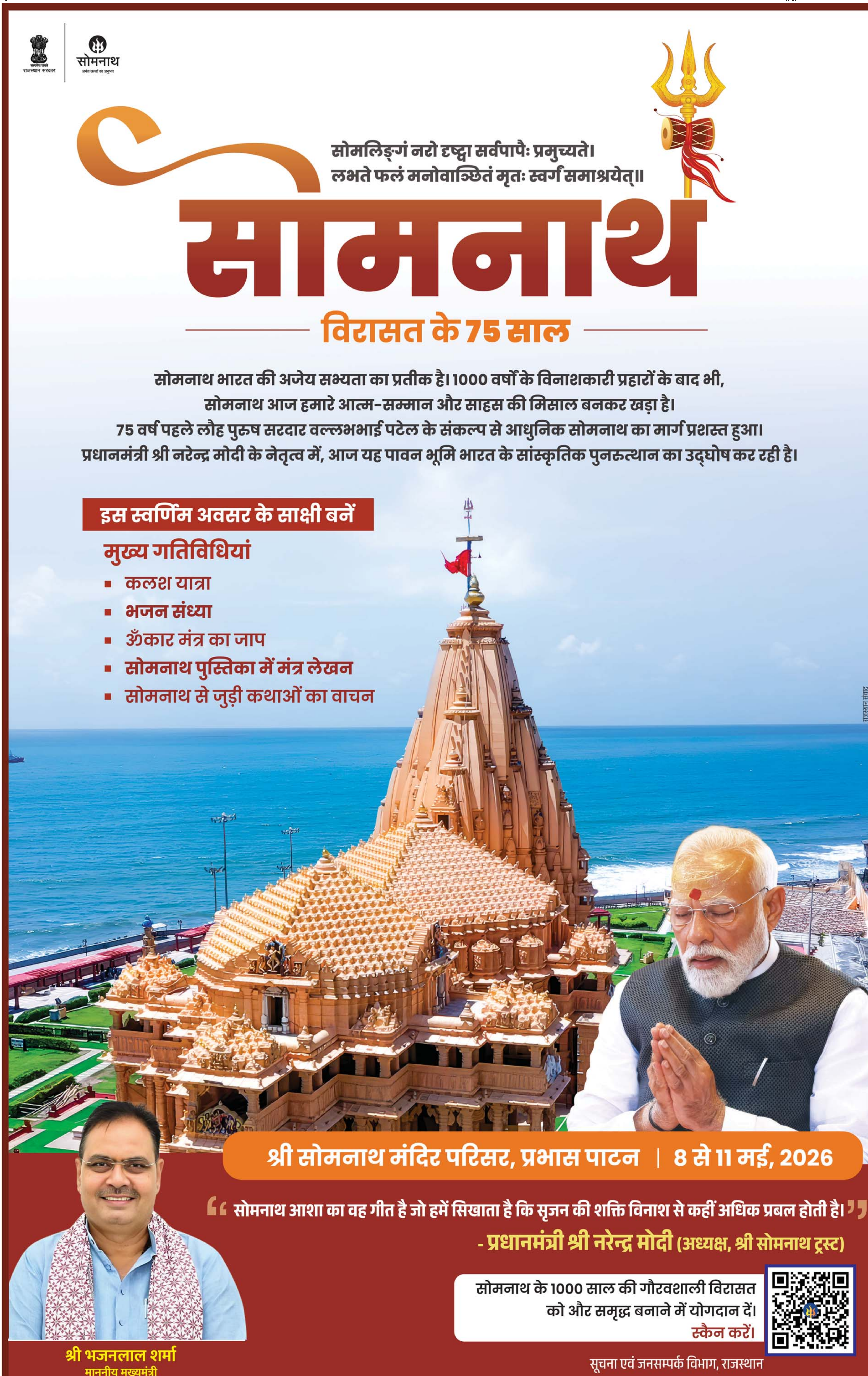
सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार
सोमनाथ
अनंत ऊर्जा का अनुभव
सोमलिङ्गं नरो दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते।
लभते फलं मनोवाञ्छितं मृतः स्वर्गं समाश्रयेत्॥
सोमनाथ
विरासत के 75 साल
सोमनाथ भारत की अजेय सभ्यता का प्रतीक है। 1000 वर्षों के विनाशकारी प्रहारों के बाद भी,
सोमनाथ आज हमारे आत्म-सम्मान और साहस की मिसाल बनकर खड़ा है।
75 वर्ष पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के संकल्प से आधुनिक सोमनाथ का मार्ग प्रशस्त हुआ।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, आज यह पावन भूमि भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का उद्‌घोष कर रही है।
इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बनें
मुख्य गतिविधियां
▪ कलश यात्रा
▪ भजन संध्या
▪ ॐकार मंत्र का जाप
▪ सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन
▪ सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन
श्री सोमनाथ मंदिर परिसर, प्रभास पाटन | 8 से 11 मई, 2026
“सोमनाथ आशा का वह गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।”
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी (अध्यक्ष, श्री सोमनाथ ट्रस्ट)
सोमनाथ के 1000 साल की गौरवशाली विरासत
को और समृद्ध बनाने में योगदान दें।
स्कैन करें।
श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान
राजस्थान संवाद

यह मुद्दा केवल पैसे का नहीं बल्कि सम्मान का है। उनके अनुसार खिलाड़ी खेल को जितना देते हैं, उसके मुकाबले उन्हें उतना सम्मान और लाभ नहीं मिल रहा है। - यानिक सिनर

विश्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी, फ्रेंच ओपन में इनामी राशि को लेकर बोलते हुए।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी — क्रिस्टियानो रोनाल्डो

दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुरुवार को सऊदी प्रो लीग में अपना 100वां गोल दागकर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। रोनाल्डो के गोल की बदौलत अल-नस्र ने अल-शबाब को 4-2 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर अपनी बढ़त मजबूत कर ली।

41 वर्षीय रोनाल्डो ने मैच के 75वें मिनट में सादियो माने के क्रॉस पर शानदार फिनिश करते हुए यह खास मुकाम हासिल किया। यह उनके पेशेवर करियर का 971वां गोल भी रहा। मौजूदा सत्र में रोनाल्डो अब तक 26 लीग गोल कर चुके हैं।

क्या आप जानते हैं ?... ओलंपिक में व्यक्तिगत रिकॉर्ड : नेविल डिसूजा (1956 ओलंपिक में एक मैच में 4 गोल, किसी भारतीय का सबसे बड़ा रिकॉर्ड)।

बीसीसीआई एनसीए अंडर-16 ट्रेनिंग कैंप जयपुर में होगा

जयपुर 8 मई। बीसीसीआई के सत्र 2025-26 की राष्ट्रीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले विभिन्न राज्यों के युवा खिलाड़ियों के एनसीए द्वारा आयोजित होने वाले ट्रेनिंग कैंप का आयोजन आरसीए अकादमी, सवाई मान सिंह स्टेडियम में आगामी तारीख 11 मई से 6 जून 2026 के दौरान किया जाएगा। एनसीए ट्रेनिंग कैंप में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के युवा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। स्वर्णव श्रीहित गुरु दास, अधविक ईश्वरन, सुकृता. जे, के भानु हर्षा, पैला श्याम दिनेश, हार्दिक शर्मा, अनाया नेगी, त्रिनाभ शुक्ला, अभिषेक राजपूत, शिवम मत्री, ऋषभ सदके, श्रेयश फडतारे, अद्वैत भट, युवराज सिंह, त्रिपर्णा सामंत, आशुतोष कुमार नाइक, कृव पटेल, अर्नव घोडगांवकर, आलोक कुमार, निर्मिक योगेश चारडे, महर्षि प्रीतेशभाई वाघेला, आर्यन त्यागी, विराज माहेश्वरी, पंकज भाटी, शोभग सिंह भाटी। हर्षद खादीवाले बैटिंग कोच, शिब शंकर पॉल बॉलिंग कोच, मंदार साने बॉलिंग कोच, एस. विगनेश फील्डिंग कोच, अभिजीत सिंह सायल फिजियोथेरेपिस्ट, वीरमणि फिजियोथेरेपिस्ट, पूर्णेंदु शेखर जेना स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, भवनेश कुमार स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, अजिंक्य विनोद सावले परफॉर्मेंस एनालिस्ट।

मैत्री क्लब ने संस्कार एकेडमी को चार विकेट से हराया

जयपुर, 8 मई। जयपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अनुराग मिश्रा स्मृति बी डिवीजन लीग में आज खेले गए पूल बी के मैच में मैत्री क्लब ने संस्कार एकेडमी को 4 विकेट से हराया। जी आर ग्राउंड पर संस्कार एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरव कुमार के 111 रन (106 गेंद, 15 चौके व एक छक्का), पारस के 20 रन व खुशवंत सिंह के 13 रनो से 43 ओवर में 191 रन बनाए। मैत्री क्लब के लिए हसन खान ने 50 पर 3, मौलिक झरवाल ने 43 पर 2, अरशद, नीतीराज व वरदान ने एक एक विकेट लिया। जवाबी पारी में मैत्री क्लब ने रामदीप के 20 रन, आयुष आमेरिया के 30 रन, वरदान शर्मा के 94 रन व क्षितिज के 23 रनो से 33.3 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन बनाकर मैच जीत लिया। संस्कार एकेडमी के लिए कार्तिक माहेश्वरी ने 34 पर 2, पुलकित माथुर ने 31 पर 2 व प्रणव शर्मा ने 26 पर एक विकेट लिया।

आदित्य टांक की गेंदबाजी से मान क्लब 233 पर सिमटी, खूबेब की फिप्टी

जयपुर, 8 मई जयपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित के एम रूंगटा ट्रॉफी के अंतर्गत आज से खेले गए तीन दिवसीय मैच के पहले दिन टीम सी (मान क्लब) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लोकेश सैनी के 22 रन, मोहित भगतानी के 20 रन, आदित्य झाला के 23 रन, मोहम्मद खूबेब के 71 रन, चिराग शर्मा के 20 रन व रिहान अली के नाबाद 20 रनो से 60.5 ओवर में 233 रन बनाकर आउट हुई।

आईपीएल 2026 पर 'हनी ट्रैप' का साया, बीसीसीआई का बड़ा एक्शन

आईपीएल में अब नहीं चलेगी मनमानी, खिलाड़ियों पर लगेगी लगाम : शुक्ला

नई दिल्ली, 8 मई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को कहा कि शीर्ष क्रिकेट निकाय इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान खिलाड़ियों के लिए नए एक्सेस कंट्रोल नियम लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य अनुशासन को मजबूत करना और टूर्नामेंट प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना है।

लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए शुक्ला ने कहा कि आईपीएल के नए नियम खिलाड़ियों की पहुंच को सीमित करेंगे और होटलों, टीम बसों और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में क्रिकेटरों के साथ अनधिकृत बैठकों को रोकेंगे। यह कदम पारदर्शिता में सुधार लाने और टूर्नामेंट के दौरान समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष ने कहा कि बीसीसीआई नए नियम बना रहा है। खिलाड़ियों की पहुंच नियंत्रित की जाएगी; आईपीएल की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनधिकृत लोगों को खिलाड़ियों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, न तो होटलों में और न ही बसों में। उनकी यह टिप्पणी बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा सीजन में खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों और अनधिकृत व्यक्तियों से जुड़ी कई अनियमितताओं के मद्देनजर बोर्ड सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी को सख्त सलाह जारी करेगा।

सैकिया ने खुलासा किया कि बीसीसीआई ने स्थापित भ्रष्टाचार-विरोधी और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कई उल्लंघन देखे हैं, जिनमें अनधिकृत व्यक्तियों का टीम सदस्यों के साथ आना, टीम होटलों में प्रवेश करना और खिलाड़ियों या अधिकारियों के कमरों में घुसना शामिल है। उन्होंने फ्रेंचाइजी मालिकों और अधिकारियों द्वारा खिलाड़ियों से प्रतिबंधित क्षेत्रों में बातचीत करने पर भी चिंता व्यक्त की, जहां आईपीएल नियमों के तहत इस तरह की पहुंच की अनुमति नहीं है। मामले को गंभीर बताते हुए, सैकिया ने कहा कि बीसीसीआई और आईपीएल शासी निकाय टूर्नामेंट प्रोटोकॉल के अनुपालन को मजबूत करने के लिए एक औपचारिक सलाह जारी करेंगे।

उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी उल्लंघन पर बोर्ड द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने आईपीएल में खिलाड़ियों के लिए नए एक्सेस कंट्रोल नियम लागू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ाना है; इन नियमों के तहत होटलों और टीम बसों में अनधिकृत व्यक्तियों को क्रिकेटरों से मिलने की अनुमति नहीं होगी।

भारतीय टीम में होगा बड़ा बदलाव!

सूर्यकुमार की जगह श्रेयस को बनाया जा सकता है कप्तान ?

नई दिल्ली, 8 मई। भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) नेतृत्व में बदलाव की तलाश में है और सूर्यकुमार यादव को भारत के टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान के पद से हटाकर श्रेयस अय्यर को उनकी जगह कप्तान बनाया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि सूर्यकुमार यादव पहले से ही 35 वर्ष के हैं और हाल ही में उन्होंने भारत को टी20 विश्व कप जिताया था। वहीं, श्रेयस अय्यर अपने चरम पर हैं और इस प्रारूप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 के फाइनल तक पहुंचाना और कोलकाता नाइट राइडर्स को 2024 में तीसरा आईपीएल खिताब दिलाना शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ता सूर्यकुमार यादव के खराब प्रदर्शन से तंग आ चुके हैं और टीम में कुछ नए खिलाड़ियों को शामिल करना चाहते हैं। यह दिलचस्प है कि भारतीय टीम जल्द ही आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच होंगे। इस सीरीज में श्रेयस अय्यर टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की कमान संभाल सकते हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के मामले में भारतीय टीम का शेड्यूल काफी व्यस्त है। 2028 में होने वाले टी20 विश्व कप और लॉस एंजिल्स ओलंपिक को देखते हुए, भारतीय टीम लगातार तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के लिए अपनी टीम में बड़े बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सूर्यकुमार यादव का बल्ले से खराब प्रदर्शन भारत के अगले टी20 कप्तान के रूप में उनकी भूमिका में बदलाव का एक प्रमुख कारण हो सकता है। उन्होंने टी20 विश्व कप में नौ पारियों में 242 रन बनाए, जिनमें से 84 रन उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बनाए थे। भारतीय कप्तान मौजूदा आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, जहां पांच बार की चैंपियन टीम अंक तालिका में नौवें स्थान पर है।

कोलकाता ने दिल्ली को 8 विकेट से हरा लगातार चौथा मैच जीता

एलन का शतक

नई दिल्ली, 8 मई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने फिन एलन की दमदार शतकीय पारी की बदौलत 34 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। कोलकाता ने 14.2 ओवर में दो विकेट पर 147 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। दिल्ली के लिए आशुतोष शर्मा ने सर्वाधिक 39 रन बनाए। इसके जवाब में कोलकाता की शुरुआत खराब रही। टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे रन आउट हुए।

अंगकृष रघुवंशी एक रन ही बना पाए। इसके बाद फिन एलन और कैमरन ग्रीन ने विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 64 गेंद में 116 रन की साझेदारी हुई। फिन ने 47 गेंद में नाबाद 100 रन और ग्रीन ने 27 गेंद में 33 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स को केएल राहुल और पथुम निसांका ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी हुई। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 14 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए। कार्तिक त्यागी ने उन्हें आउट किया। नितीश राणा 8 रन बनाकर ग्रीन का शिकार बने। समीर रिजवी 7 गेंद में तीन रन ही बना सके। ट्रिस्टन स्टब्स 4 गेंद में दो रन बनाकर आउट हुए।

एलन-ग्रीन में शतकीय साझेदारी

143 रन का टारगेट चेज कर रही कोलकाता ने 31 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे। कप्तान अजिंक्य रहाणे 13 और अंगकृष रघुवंशी एक रन बनाकर आउट हुए थे। ऐसे में फिन एलन ने कैमरन ग्रीन के साथ शतकीय साझेदारी करके टीम को जीत दिला दी।

11वें ओवर में कोलकाता के फिन एलन ने फिफ्टी पूरी की। उन्होंने मिचेल स्टार्क की पहली बॉल पर छक्का लगाया। इसी छक्के से उनकी फिफ्टी पूरी हुई। इतना ही नहीं, कैमरन ग्रीन के साथ अर्धशतकीय साझेदारी भी हुई।

पाथुम निसांका ने फिफ्टी लगाई

ओपनर पाथुम निसांका ने 29 बॉल पर 50 रन की पारी खेली। जबकि आशुतोष शर्मा ने 39 रन का योगदान दिया। केएल राहुल ने 23 रन बनाए। कोलकाता की ओर से अनुकूल रॉय और कार्तिक त्यागी ने 2-2 विकेट झटके। वैभव अरोड़ा, सुनील नरेन और कैमरन ग्रीन को एक-एक विकेट मिला। एक बैटर रनआउट हुआ।

ग्रीन के छक्के से कोलकाता 100 पार

12वें ओवर में कोलकाता ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। कैमरन ग्रीन ने कुलदीप यादव की तीसरी बॉल छक्का लगाकर टीम को ट्रिपल डिजिट तक पहुंचाया। फिन एलन ने ओवर की पहली बॉल पर छक्का लगाया।

राजस्थान रॉयल के नए मालिक लक्ष्मी निवास मित्तल ने बेटे के साथ एसएमएस स्टेडियम पर टीम को अभ्यास करते देखा।

मैग्नस कार्लसन ने अर्जुन एरिगैसी को हराकर 'टेपे सिगेमैन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट 2026' का खिताब जीता

माल्मो, 8 मई। विश्व नंबर-1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने गुरुवार को भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी को सडन डेथ प्लेऑफ में हराकर 'टेपे सिगेमैन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट 2026' का खिताब अपने नाम कर लिया। मुख्य टूर्नामेंट में अपराजित रहने वाले अर्जुन एरिगैसी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन खिताबी मुकाबले में उन्हें मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। टाईब्रेकर की दो बाजियों में दोनों खिलाड़ियों ने एक-एक जीत दर्ज की, जिसके बाद मुकाबला सडन डेथ तक पहुंचा, जहां कार्लसन ने बाजी मार ली।

राजधानी

प्रदेश में पूर्व विधायकों को यथावत मिलती रहेगी पैंशन

राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पूर्व विधायकों को दी जा रही पेंशन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश मिलाप चंद डांडिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में राजस्थान विधानसभा अधिकारी और सदस्य वेतन, परिलब्धियां और पेंशन अधिनियम,1956 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विधायकों और सांसदों को मिलने वाले लाभों की संवैधानिक स्थिति लगभग एक समान है। सुप्रीम कोर्ट सांसदों के मामले में पेंशन का मुद्दा पहले ही तय कर चुका है और यह अब अनसुलझा कानूनी प्रश्न नहीं है। अदालत ने माना की पेंशन केवल पारंपरिक सरकारी सेवा या नियोक्ता व कर्मचारी संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून में कई अन्य श्रेणियों में भी पेंशन को मान्यता दी गई है। अदालत ने कहा कि संविधान के तहत विधान मंडल को पेंशन के संबंध में कानून बनाने की पूर्ण विधायी क्षमता है। संविधान के अनुच्छेद 195 में पेंशन शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता की संविधान में इसे देने पर कोई प्रतिबंध है। इसके अलावा कानून बनाना मुख्य रूप से विधानमंडल का काम है और न्यायिक समीक्षा का दायरा विधायी क्षमता की जांच करने तक सीमित है।

जनहित याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने साल 1956 के अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 195 केवल वेतन और भत्तों के निर्धारण की शक्ति देता है और इसमें पेंशन का हवाला नहीं है। ऐसे में विधानसभा को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा पेंशन केवल सरकारी सेवा से रिटायर होने पर ही दी जाती है, जबकि विधायक का पद राजनीतिक और संवैधानिक पद है। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लोक प्रहरी के मामले में सांसदों को पेंशन देने का मुद्दा पहले ही तय चुका है। सांसदों और विधायकों की स्थिति एक समान है, इसलिए विधानसभा की ओर से बनाया कानून पूरी तरह वैध है। संविधान भी पेंशन के संबंध में विधानसभा को कानून बनाने की अधिकार देता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

हवामहल के सामने युवती को टक्कर मारने वाला टैक्सी ड्राईवर गिरफ्तार

जयपुर । पुलिस थाना माणक चौक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हवामहल के सामने एक युवती को लापरवाही से टक्कर मार कर घायल करने वाले टैक्सी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हादसे में प्रयुक्त टैक्सी कार को भी बरामद कर लिया है। पुलिस उपायुक्त (जयपुर उत्तर) करण शर्मा ने बताया कि एक युवक ने थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 5 मई की रात जब वह अपने मित्रों के साथ हवा महल घूमने आया था, तब वापस लौटते समय एक टैक्सी कार के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और प्रार्थी की महिला मित्र को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी चालक घायल की मदद करने या पुलिस को सूचना देने के बजाय मौके से फरार हो गया। जांच में सामने आया कि हादसे के दिन टैक्सी चालक हवा महल के सामने से गुजर रहा था।

कपड़ा फैक्ट्री में करोड़ों रु. का आईपीएल सट्टा पकड़ा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) और मालपुरा गेट थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कपड़ा फैक्ट्री में संचालित अवैध सट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत छह सटोरियों को गिरफ्तार कर करोड़ों रुपए के हिसाब-किताब से जुड़े रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वाहन जब्त किए हैं। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) संजीव नैन ने बताया कि पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और विशेष पुलिस कमिश्नर (ऑपरेशन्स) ओमप्रकाश के निर्देशन में सीएसटी ने यह कार्रवाई की। जहां मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मालपुरा गेट इलाके में माल की ढाणी (सांगानेर) स्थित नानग विहार कॉलोनी के प्लॉट नंबर-3 में संचालित 'चिरायु गर्वित कम्पनी' नामक कपड़ा फैक्ट्री पर दबिश दी। पुलिस ने फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में दबिश देकर आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते उत्तम सैनी (40) निवासी झालाना ग्राम, रूपल बंसल (34) निवासी मुहाना मंडी रोड, राजेंद्र कुमार (46), निवासी पुरानी टोंक,देवेंद्र कुमार जंगलानी (37) निवासी मालवीय नगर, विकास नागर (40) निवासी नाहरी का नाका और मनोहर स्वामी (38) निवासी बाबाजी की ढाणी, सांगानेर को गिरफ्तार किया। पुलिस जब पहुंची, तब लखनऊ और बेंगलुरु के बीच खेले जा रहे आईपीएल मैच पर आरोपियों द्वारा दांव लगाए जा रहे थे।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपित मालवीय नगर के बड़े बुकी अशोक गुप्ता और बाबू उर्फ नोनी से सट्टे की लाइन लेकर जूम एप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी लंबे समय से कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बुकी उत्तम सैनी और फैक्ट्री मालिक मनोहर इस कारोबार में बराबर के पार्टनर थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 डोंगल, चार्जर केबल, कैलकुलेटर, सट्टे के हिसाब-किताब से जुड़े 6 रजिस्टर तथा 1540 रुपए नकद बरामद किए।

इसके अलावा एक लग्जरी स्कॉर्पियो , होंडा डियो स्कूटी , एक्टिवा स्कूटी और पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई।पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीएसटी के एसआई संदीप बसेरा, एएसआई कमल डागर और कांस्टेबल कुमेर गुर्जर की कार्रवाई में विशेष भूमिका रही।

अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना बनी विद्यार्थियों का सशक्त संबल

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों (बालकों) के लिए एक सशक्त सहारा बनकर उभर रही है। विगत ढाई वर्षों में 11 करोड रूपये से अधिक व्यय कर 7314 छात्रों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से उन छात्रों (बालकों) को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जो उच्च शिक्षा के लिए अपने गृह स्थान से दूर रहकर जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में अकादमिक पाठयक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं, तथा किराये का मकान लेकर अथवा पेईंग गेस्ट के रूप में रह रहे हैं। पूर्णत: राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित इस योजना के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय) के विद्यार्थियों को आवास, भोजन एवं बिजली-पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए 2000 प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे छात्रों (बालकों) को प्रति वर्ष 20 हजार तक का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, जो उनकी शिक्षा यात्रा को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत 5000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1500-1500, अन्य पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 750-750 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 छात्रों को शामिल किया है।

आमेर-नाहरगढ़-जयगढ़ रोपवे की प्रारंभिक मंजूरी पर अंतरिम रोक

हाईकोर्ट ने 2 फरवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और निजी कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने आमेर-नाहरगढ़-जयगढ़ पर रोपवे बनाने के लिए निजी कंपनी को दी प्रारंभिक मंजूरी के गत 2 फरवरी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और निजी कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश शिवमप्राइम इंफा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता अभि गोयल ने बताया कि राज्य सरकार ने आमेर- नाहरगढ -जयगढ पर रोपवे निर्माण की घोषणा की थी। जिसमें याचिकाकर्ता सहित तीन कंपनियों ने जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन किया था। याचिका में कहा गया कि गत 2 फरवरी को निजी कंपनी को रोपवे के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी गई, जबकि उनकी ओर से परियोजना की लागत करीब 350 करोड रुपए बताई गई। जिसमें वन क्षेत्र का भारी दोहन होने की भी संभावना है। इसके अलावा याचिकाकर्ता की ओर से परियोजना की लागत केवल 80 करोड रुपए की बताई गई है और वन भूमि का कम से कम दोहन की भी जानकारी दी गई। इसके बावजूद भी उस कंपनी को रोपवे के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी गई। याचिका में कहा गया।

कि इस लागत से रोपवे बनने पर आमजन के लिए टिकट भी अधिक राशि का वसूल किया जाएगा और वन भूमि का भी अधिक दोहन होगा।

नकली सोने की ईंट बेचने वाले मेवात गैंग के दो शातिर गिरफ्तार

जयपुर। कानोता थाना पुलिस ने नकली सोने की ईंट बेचकर लोगों से ठगी करने वाले मेवात क्षेत्र के एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 ग्राम वजनी पीली धातु की नकली सोने की ईंट, दो मोबाइल फोन, दो फर्जी सिम कार्ड तथा वारदात में प्रयुक्त काले रंग की लग्जरी स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। दोनों आरोपी कई अन्य मामलों में भी वांछित बताए जा रहे हैं।

पुलिस उपायुक्त (जयपुर पूर्व) रंजीता शर्मा ने बताया कि कानोता थाना पुलिस ने नकली सोने की ईंट बेचकर लोगों से ठगी करने वाले मेवात क्षेत्र के एक शातिर बदमाश रासीद उर्फ भूरा (33) पुत्र हारूण निवासी गांव जाज्मका, थाना कैथवाड़ा जिला डीग तथा जाकिर हुसैन (42) पुत्र नूर मोहम्मद निवासी अकबरपुर मेव, थाना सीकरी जिला डीग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार रासीद उर्फ भूरा के खिलाफ पूर्व में अलवर जिले के नौगांवा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और वह जेल भी जा चुका है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मेवात क्षेत्र के रहने वाले हैं और सीधे-साधे तथा संपन्न लोगों को निशाना बनाकर ठगी करते थे। आरोपी पहले कम कीमत में सोना बेचने का झांसा देते और विश्वास जीतने के लिए असली सोने का छोटा टुकड़ा जांच के लिए देते थे। बाद में सुनसान स्थान पर बुलाकर नकली सोने की ईंट थमा लाखों रुपए लेकर फरार हो जाते थे। कानोता थानाधिकारी मुनीन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी।

हैदराबाद में 200 करोड़ रूपए के फूड पार्क, सीड एवं फूड प्रोसेसिंग के एमओयू

मुख्यमंत्री भजनलाल ने हैदराबाद में ग्राम-2026 के तहत इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित किया

हैदराबाद/जयपुर, 8 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर एग्रीटेक एवं फूड प्रोसेसिंग के सुनहरे अवसरों की भूमि बन चुका है। कृषि पैदावार में विविधता के कारण राजस्थान में प्रसंस्करण उद्योग, कोल्ड चेन, स्पाइस पार्क एवं कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार प्रदेश को कृषि आधारित उद्योगों और वैल्यू एडेड

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान प्रदेश को कृषि आधारित उद्योगों और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का वैश्विक केन्द्र बनाने की दिशा में प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित किया।

प्रोडक्ट्स का वैश्विक केन्द्र बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 'पधारो म्हारो देस' का आ ान करते हुए, निवेशकों, एग्री-टेक स्टार्टअप्स और विशेषज्ञों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद आज देश का प्रमुख आईटी और एग्री इनोवेशन हब बन चुका है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का लैब टू लैंड मॉडल राजस्थान के लिए प्रेरणादायी है और राज्य सरकार इसे और अधिक मजबूती से लागू करना चाहती है।

इन्वेस्टर्स मीट में राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर फूड पार्क, सीड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न एमओयू का आदान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में वन-टू-वन बिजनेस मीटिंग्स एवं निवेशकों, उद्योग जगत और एग्रीटेक विशेषज्ञों के साथ संवाद' किया गया।

इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल, आईसीआरआईएसएटी के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक, फिक्की नेशनल एग्रीकल्चर कमेटी के सह-अध्यक्ष सुब्रतो गीस सहित, कृषि विभाग, राजस्थान फाउंडेशन के हैदराबाद चैप्टर के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स उद्यमी एवं निवेशक उपस्थित थे।

बाइक हाइवे पर खड़े ट्रक में घुसी, पति-पत्नी व तीन बच्चों की मौत

बुलंदशहर, 08 मई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शुक्रवार को एनएच-34 पर हुए एक हादसे में ट्रक से टकरा कर बाइक सवार माता- पिता और तीन बच्चों व सहित, कुल पांच लोगों की मौत हो गयी। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे का शिकार हुआ परिवार वैष्णो देवी धाम के दर्शन कर लौटा था और रिश्तेदार के घर रुकने के बाद आज अपने गांव लौट रहा था।

जानकारी के अनुसार, बुलंदशहर में खुर्जा की तरफ से उत्तम सिंह बाइक से पत्नी और तीन बच्चों के साथ बुलंदशहर नगर के धमेड़ा अड्डा की तरफ अपने घर आ रहे थे। देहात कोतवाली में एनएच-34 पर भंसौली कट के पास बाइक सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही पांचों की मौत हो गई। मृतकों में उत्तम, उनकी पत्नी उर्मिला, बेटा निशांत, बेटी दिशा और मासूम अनायरा शामिल हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

आरपीएससी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द की

सितंबर 2026 में नई परीक्षा होगी, जिसमें केवल वे शामिल होंगे जिन्होंने पिछली परीक्षा दी थी

अजमेर, 8 मई (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार के कड़े रुख और सिफारिश के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। लंबे समय से विवादों और धांधली के आरोपों से घिरी सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को आयोग ने आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। प्रदेश के लाखों युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए अब यह परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ नए सिरे से आयोजित की जाएगी।

■ राजस्थान लोक सेवा आयोग 16 मई से पोर्टल पर आवेदन संशोधन की प्रक्रिया शुरु करेगा।

आयोग के अनुसार, नई परीक्षा के सितंबर 2026 में आयोजित होने की प्रबल संभावना है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार कोई नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस री-एग्ज़ाम में केवल 3 लाख 83 हजार 097 अभ्यर्थी ही बैठ सकेंगे। यह मौका सिर्फ उन युवाओं को मिलेगा, जो 13 से 15 सितंबर 2021 के बीच आयोजित हुई लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में भौतिक रूप से उपस्थित हुए थे। यदि किसी अभ्यर्थी ने 2021 में फॉर्म भरा था लेकिन परीक्षा नहीं दी थी, या सिर्फ एक ही पेपर दिया था, तो उसे अब इस नई परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। चूंकि परीक्षा लगभग 5 साल के अंतराल के बाद दोबारा हो रही है, इसलिए आयोग ने अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार करने का अवसर दिया है।

आगामी 16 मई से पोर्टल पर आवेदन संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी अपने दस्तावेजों, पते या अन्य आवश्यक विवरणों में इस दौरान सुधार कर सकेंगे।

आयोग ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपने फॉर्म अपडेट कर लें, ताकि बाद में एडमिट कार्ड जारी करने या चयन प्रक्रिया में कोई तकनीकी अड़चन न आए।

गौरतलब है कि एसआई भर्ती 2021 परीक्षा के आयोजन के बाद से ही इसके पेपर लीक होने व इसमें और डमी कैंडिडेट बिठाने जैसे गंभीर आरोप लगते रहे थे। मामला राज्य सरकार और पुलिस के संज्ञान में आने के बाद कई गिरफ्तारियां भी हुई थीं।

ज्ञातव्य है कि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला दिया था। उसी के तहत राज्य सरकार ने राज्य लोकसेवा आयोग से एसआई भर्ती परीक्षा-2021 रद्द करने की सिफारिश की। इसके बाद आयोग ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है।

नासिक टीसीएस धर्मान्तरण मामले की मुख्य आरोपी निदा खान गिरफ्तार

कोर्ट ने निदा खान को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

नासिक, 08 मई। महाराष्ट्र के नासिक के बहुचर्चित टीसीएस धर्मांतरण मामले में मुख्य संदिग्ध आरोपी निदा खान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले एक महीने से पुलिस को चकमा दे रही निदा खान को नासिक और छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को उसे नासिक रोड न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद, निदा खान फरार हो गई थी। विशेष जांच दल (एसआईटी) को सूचना मिली थी कि वह छत्रपति संभाजीनगर के नारेगांव इलाके में छिपी हुई है। इसके बाद नासिक पुलिस

■ पता चला है कि छत्रपति संभाजीनगर के नगर सेवक मतीन माजिद पटेल ने निदा खान को शरण दे रखी थी, पटेल को भी आरोपी बनाया गया है।

आयुक्त संदीप कर्णिक ने छत्रपति संभाजीनगर के पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार से संपर्क कर संयुक्त अभियान शुरू किया।

जांच में सामने आया कि स्थानीय नगरसेवक मतीन माजिद पटेल ने निदा खान को शरण दी थी। सादे कपड़ों में 20 से अधिक पुलिसकर्मी दो दिनों से इलाके पर नजर बनाए हुए थे। अंततः बिना नंबर वाले वाहनों की मदद से बेहद गोपनीय तरीके से निदा खान को हिरासत में लिया गया।

फरारी के दौरान निदा खान ने नासिक, भिवंडी, मुंब्रा और छत्रपति संभाजीनगर सहित कई स्थानों की यात्रा की। पुलिस के अनुसार, उसने तकनीकी निगरानी से बचने की कोशिश की, लेकिन डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए पुलिस उसके करीब पहुंच गई।

जांच एजेंसियों को उसके मोबाइल फोन से अहम डिजिटल सबूत मिलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि मोबाइल में पीड़िता को धर्मांतरण के लिए उकसाने वाले कथित वीडियो और संदेश मौजूद हैं। डेटा रिकवर होने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए नासिक रोड अदालत में सुनवाई 'इन कैमरा' तरीके से की गई। अदालत परिसर के बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था।

सरकारी पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील अजय मिसर ने पुलिस हिरासत की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के वकील राहुल कासलीवाल और बाबा सैयद ने निदा खान के गर्भवती होने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की। हालांकि अदालत ने यह दलील खारिज करते हुए पुलिस हिरासत मंजूर कर ली। मुख्य आरोपी निदा खान को शरण देने वाले नगरसेवक मतीन पटेल को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक ने कहा, जांच में बाधा डालने या आरोपियों की मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

रेजिडेंसियल स्कूल में निर्माण के लिये 800 साल पुराना मंदिर तोड़ा

हैदराबाद, 08 मई। तेलंगाना के वारंगल जिले में एक यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के निर्माण के लिए 800 साल पुराने काकतीय कालीन शिव मंदिर को बुलडोजर से ढ हा दिया गया, जिससे आक्रोश और कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। खानपुर मंडल के अशोक नगर में हुई इस घटना पर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएचए) में शिकायत के बाद केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय और पुरातत्व विभाग ने मामला दर्ज कर लिया है।

■ राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में शिकायत के बाद संस्कृति मंत्रालय व पुरातत्व विभाग ने मामला दर्ज किया।

वकील इम्मनेनी रामा राव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि काकतीय शासक गणपति देव (1199-1262 ईस्वी) के शासनकाल के इस शिव मंदिर को खानापुर मंडल में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के निर्माण के लिए भारी मशीनों से नष्ट कर दिया गया। शिकायत में कहा गया कि अधिकारियों ने तेलंगाना हेरिटेज एक्ट के तहत अनिवार्य विरासत संरक्षण समिति का गठन नहीं किया। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि मंदिर को ध्वस्त करने के बजाय उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता था।

रिपोर्टों के अनुसार मंदिर के गर्भगृह को खोदा गया था, जिससे यह संदेह पैदा हो गया है कि ठेकेदार ने नीचे दबे कथित खजाने की तलाश में इसे नष्ट किया होगा। हालांकि जिला प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन किय। वारंगल जिला कलेक्टर कार्यालय के अनुसार छह मई को किए गए संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि जमीन पर भारी झाड़ियां और पेड़ उगे हुए थे।

बिहार में बिजली गिरने से 7 की मौत

पटना, 08 मई। बिहार के विभिन्न जिलों में शुक्रवार देर शाम आये आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से सात लोगों की मौत हो गई।

राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से भोजपुर में 01, पटना में 01, समस्तीपुर में 01 और पूर्वी चंपारण में 01 तथा आंधी-तूफान/तेज वर्षा से पेड़ गिरने के कारण दबकर पटना में 02 एवं वैशाली में 01 व्यक्ति की मृत्यु पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।

'अनिल अंबानी की कंपनियों के बैंकिंग फ्रॉड की गहन जांच हो'

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की

नई दिल्ली, 08 मई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में एक गहन जांच की जरूरत है। यह मामला तब सामने आया, जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बताया कि सात मामलों में अनुमानित कुल नुकसान लगभग 27,337 करोड़ रुपये है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ, पूर्व नौकरशाह ई.ए.एस. शर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली एडीएजी फर्मों द्वारा 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित ऋण धोखाधड़ी में अदालत की निगरानी वाली जांच की मांग की गई थी।

■ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक जांच एजेंसी अनिल अंबानी की गिरफ्तारी की मांग नहीं करती वह इसका आदेश नहीं दे पाएगी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों ने इसे 27,000 करोड़ रुपये का घोटाला बताया है। अनिल अंबानी को इसका किंगपिन कहा है, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।

पीठ ने इस बात पर गौर किया कि शीर्ष अदालत ने बार-बार कहा है कि जब तक जांच एजेंसी की ओर से गिरफ्तारी की मांग नहीं की जाएगी, वह इसका निर्देश देने में संकोच करेगी। पीठ ने कहा कि जांच को सनसनीखेज बनाने के बजाय, ध्यान जांच और प्रासंगिक सामग्री के संग्रह पर होना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि किसी मामले में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता जांच एजेंसी के विवेक पर छोड़ दी जानी चाहिए।

जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के खिलाफ एसबीआई द्वारा दर्ज शिकायतों पर दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। उन्होंने कहा, "कुल नौ प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें से सात जांच के अधीन हैं और दो में आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। सात मामलों में, कुल 27,337 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।"

मेहता ने बताया कि त्वरित जांच के लिए कई जांच अधिकारियों की कई टीमें बनाई गई थीं, और जिन सात मामलों में जांच चल रही थी, उनमें 14 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। उन्होंने कहा कि 31 लुक-आउट सर्कुलर जारी किए गए हैं और इन मामलों में लगभग 3,960 दस्तावेज एकत्र किए गए हैं। मेहता ने यह भी बताया कि इन मामलों में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उन्होंने इन सात मामलों में आरोप पत्र दायर करने के लिए एक अस्थायी समय-सीमा भी दी।

अनिल अंबानी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि जब संबंधित अदालत ने अभी तक आरोप पत्र पर संज्ञान नहीं लिया है, तो याचिकाकर्ता को एक आरोप पत्र की प्रति कैसे मिल सकती है।

आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरा होने पर मैराथन आयोजित किया

नई दिल्ली, 08 मई। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में शुक्रवार को यहां आकाशवाणी मुख्यालय से मैराथन का आयोजन किया गया। इसको प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गौरव द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय प्रसारक के साथ एकजुटता दिखाते हुए फिट इंडिया की भावना को बढ़ ावा देना था। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी ये मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन तथा आरबीआई भवन से होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। इस आयोजन में आकाशवाणी के कर्मचारियों के साथ-साथ भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) जैसे अर्धसैनिक बलों के जवानों ने भी दौड़ लगाकर फिट इंडिया की भावना को प्रदर्शित किया।

अजीबो-गरीब तर्क ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन के प्रति भारी और व्यापक समर्थन है, जिन्होंने पिछले पांच सालों में लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ संघर्ष का लगातार नेतृत्व किया।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "सतीशन के लिए पूर्ण समर्थन है, और अगर नेतृत्व के.सी. वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाता है, तो इतनी बड़ी फूट और मजबूत मतभेदों के बीच वे पार्टी, सरकार और राज्य नहीं चला पाएंगे।"

सभी प्रमुख हितधारकों, जिनमें वी.डी. सतीशन, रमेश चेन्नीथला, वेणुगोपाल और अन्य शामिल हैं, को दिल्ली बुलाया गया है और कल एक बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि इस मुद्दे पर चर्चा हो और पूरी प्रक्रिया में समझदारी लाई जा सके।

वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पिछले 9 वर्षों से वे संगठन के प्रभारी एआईसीसी महासचिव रहे हैं और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं।

जो लोग वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि आने वाले साल में उत्तर प्रदेश चुनाव और 2029 के आम चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी को संगठन प्रभारी के रुप में हिंदी भाषी क्षेत्र के हिंदी बोलने वाले व्यक्ति की जरूरत है, ताकि यह साबित किया जा सके कि संगठन को कुर्सी पर नया नेतृत्व चाहिए और केरल को के.सी. वेणुगोपाल की जरुरत है।

सियासी खींचतान जारी है और पार्टी का केरल संगठन और एआईसीसी इस मुद्दे पर पूरी तरह विभाजित हैं।

पार्टी की एकता बिखरी हुई है और आज केरल कांग्रेस गंभीर रूप से विभाजित है।

अरुणाचल प्रदेश में भूकंप

इटानगर, 08 मई। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिला में शुक्रवार को दोपहर बाद मध्यम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किये गये। भूकंप के चलते कहीं से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।

■ किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं।

भारतीय सिस्मोलॉजी केन्द्र के अनुसार, अरुणाचल में 04 बजकर 05 मिनट 52 सेकेंड पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई।

भूकंप का केन्द्र पापुम पारे जिला में जमीन के अंदर 05 किलोमीटर नीचे स्थित था। भूकंप का एपीक सेंटर 27.390 उत्तरी अक्षांश तथा 93.853 पूर्वी देशांत्तर पर स्थित था।

'हमारे 300 से अधिक कार्यकर्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिए आयोग स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

ममता बनर्जी की पिछली सरकार के कुछ कार्यों की जांच के लिए भी एक आयोग स्थापित किया जा रहा है।

पूरी तरह से जांच शुरू हो गई है और शुभेन्दु अधिकारी के व्यक्तिगत सहायक के हत्यारों की तलाश शुरू हो गई है, जिनकी हत्या एक दिन पहले राजनीतिक कारणों से की गई थी।

नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों द्वारा कल कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कम से कम बीस भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में शपथ ली जाएगी।

दुर्भाग्यवश, अपनी असभ्यता जारी रखते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समारोह में भाग नहीं लेंगी। इससे पहले सभी सेवानिवृत्त मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते रहे हैं।

वैसे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, ममता बनर्जी "पूर्व" शब्द जोड़ने क बजाय अब भी खुद को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं।

शुभेन्दु को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करने की घोषणा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम कोलकाता में की, जब नव निर्वाचित विधायकों का एक सम्मेलन संपन्न हुआ। भाजपा संसदीय बोर्ड ने अमित शाह को विधायकों की बैठकों की अध्यक्षता करने और नेता व मुख्यमंत्री चुनने का कार्य सौंपा था।

गृह मंत्री ने सदन के नेता और मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित नाम आमंत्रित किया था, जिस पर नव निर्वाचित विधायकों ने एकमत होकर शुभेन्दु अधिकारी का नाम ज़ोर से पुकारा। जब अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा की, तब विधायकों ने कोई अन्य वैकल्पिक नाम नहीं दिया।

लेकिन शुभेन्दु की इस शानदार जीत पर एक दुख की छाया भी थी, क्योंकि उनके युवा कार्यकारी सहायक, जो भारतीय वायुसेना के पूर्व कर्मचारी थे, की एक दिन पहले राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। भावुक अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से शोक व्यक्त किया कि उनके पी.ए. को भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र (ममता बनर्जी के गढ़) में उनकी जीत का मूल्य चुकाना पड़ा।

मौजूदा हालात में कोई और विकल्प अकल्पनीय होता। अधिकारी ने 2021 से लगातार सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी थी।

इस मोड़ पर शुभेन्दु को छोड़कर किसी अन्य उम्मीदवार को चुनने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष और निराशा पैदा होती, जो बंगाल में पार्टी के पहले कदम को ही बाधित कर सकता था। पार्टी कार्यकर्ताओं को सत्ताधारी दल द्वारा लगातार और बेरहम तरीके से प्रताड़ित किया गया। भाजपा का दावा है कि पार्टी के कम से कम 300 ग्राउंड-लेवल कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया और मारा गया, जबकि कई अन्य को प्रताड़ना और हत्या से बचने के लिए अपने घर छोड़ने पड़े।

शुभेन्दु ने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा और जहां भी पार्टी संकट में थी, वे स्वयं वहाँ पहुंचे। शुभेन्दु स्वयं हमेशा खतरे में रहे।

पार्टी अब नई शुरुआत और राज्य के लोगों की उम्मीदों की दहलीज़ पर है।

विजय आज शपथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने की सहमति दी।

शुक्रवार को चेन्नई में बातचीत हुई, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यक्तिगत रूप से वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन से बात कर टीवीके नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थन को सुनिश्चित किया।

इसके तुरंत बाद, सीपीआई कार्य समिति और सीपीएम की राज्य नेतृत्व टीम ने भी विजय का समर्थन किया, जिससे अगले सरकार बनाने को लेकर अनिश्चितता समाप्त होने की संभावना बढ़ गई।

राज्यपाल और विजय ने बुधवार और गुरुवार को भी मुलाकात की थी। दोनों बार अरलेकर ने विजय के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि टीवीके नेता के पास विधानसभा में आवश्यक समर्थन नहीं है।

लोक भवन ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि "सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन" स्थापित नहीं हुआ है।

इस निर्णय के बाद टीवीके कार्यकर्ताओं ने राज भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस ने राज्यभर में राज्यपाल और केन्द्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की।

गुरुवार को अरलेकर के निर्णय के जवाब में, कांग्रेस नेता गिरीश चौडणकर ने कहा कि राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना ही चाहिए। उन्होंने मीडिया से कहा कि बहुमत का परीक्षण केवल विधानसभा के पटल पर किया जा सकता है।

उन्होंने भाजपा एवं आरएसएस पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया, जबकि भाजपा के पास विधानसभा में केवल एक विधायक है।

तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंथगई ने 8 मई को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की अपील की, आरोप लगाते हुए कि राज्यपाल संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और टीवीके को सरकार बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

बाद में, विजय ने सीपीआई राज्य मुख्यालय का दौरा कर नेताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्कूल जाते समय मुख्यमंत्री से एक बार फिर मिलीं और अपनी मांग दोहराई, तो मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए बताया कि जाजोद के स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू हो चुका है। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इस विद्यालय में आप गणित एवं जीव विज्ञान दोनों में से अपनी रुचि अनुसार विषय चुनकर इसी साल से पढ़ाई कर सकती हैं। मुख्यमंत्री के मुंह से खुशखबरी सुनकर बच्चियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा कि उनकी मांग इतनी जल्दी पूरी होगी।

ममता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजनीतिक संदेश भी माना जा सकता है। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

टीवीके के सभी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टी कोर्ट जाने की योजना बना रही है।

द्रमुक ने शुक्रवार को एक बैठक की, जिसमें चार प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें से एक प्रस्ताव पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन को "आपातकालीन निर्णय लेने" का अधिकार देता है। प्रस्ताव के बारे में द्रमुक ने कहा, "हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक और चुनाव को टाला जाए, एक स्थिर सरकार बनाई जाए और साम्प्रदायिक ताकतों को कोई मौका न दिया जाए।"

बहुमत की कमी को "जटिल संकट" बताते हुए, द्रमुक ने अपने सभी विधायकों से कहा है कि वे 10 मई तक चेन्नई में रहें।

हालांकि, द्रमुक के शीर्ष सूत्रों ने पुष्टि की कि एक योजना पर विचार किया जा रहा है, जिसमें ई. पलानीस्वामी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और द्रमुक बाहर से समर्थन देगा।

द्रमुक के कुछ युवा नेताओं, विशेषकर उदयनिधि स्टालिन के शिविर को डर है कि विजय सत्ता में आने के बाद एम.जी. रामचंद्रन की तरह हो जाएंगे और उन्हें हटाना लगभग असंभव होगा। विख्यात एमजीआर ने जीवन भर द्रमुक को सत्ता से बाहर रखा था।

पार्टी के पुराने नेता, जिनमें एमके स्टालिन शामिल हैं, अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार, वे इस प्रयोग पर जनता की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि यह दो पार्टियों का साझा प्रयास है, जो दशकों से आमने-सामने रही हैं, और उन्हें भारी विरोध का डर है।

अन्नाद्रमुक ने भी इसी तरह का कदम उठाया है, जिसने अपने विधायकों से कहा है कि वे प्रतीक्षा करें और देखें। पार्टी के एक हिस्से को टीवीके के साथ गठबंधन की जल्दी है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है।

टीवीके ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खराब है, जिसने 23 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को हराया। अय्यर ने कहा, कांग्रेस ने पांच सीटें जीतीं, उसने ये सीटें अपने दम पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से द्रमुक के साथ अपनी दशकों पुरानी कनिष्ठ साझेदारी के बल पर जीतीं।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालयः** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालयः** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालयः** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908